



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

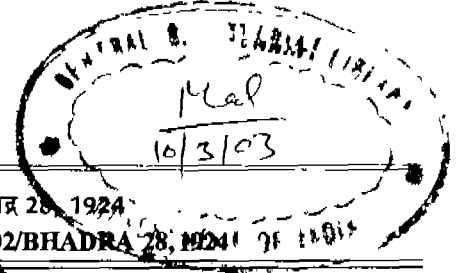
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 243]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2002/भाद्र 28, 1924

No. 243]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2002/BHADRA 28, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2002

अन्तिम जांच परिणाम

विषय:- डेनकार्म से कैटलिस्टों अर्थात् हाइड्रोडिसल्फराजेशन, जिक आक्साइड डिसल्फयूराइजेशन, हाई टैम्प्रेचर शिफ्ट, लो टैम्प्रेचर शिफ्ट सैकेन्डी रिफारमिंग और मेथानेशन कैटलिस्टों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की अन्तिम समीक्षा से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 27/1/2001-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अधीन ।

क. प्रक्रिया

नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) की उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 के धारा 9क(5) के अनुसार और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अन्तर्गत 7.5.1997 के प्राधिकारी के मूल प्रारंभिक जांच परिणामों में और 20.06.1997 के सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 56 में संकेत किया है (जिसे बाद में संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) डैनमार्क (जिसे बाद में संबद्ध देश माना गया है) के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित कैटलिस्टों के आयातों पर निरंतर लगने वाले पाटनरोधी शुल्क के पुनरीक्षण के लिए अन्तिम समीक्षा प्रारंभ की ।

(ii) प्राधिकारी ने डैनमार्क के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में यथा संशोधित, 1995 की अनुसूची-5 के सीमाशुल्क कोड 38 और 98 के अन्तर्गत वर्गीकृत है, के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए दिनांक 17.1.2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकशित किया गया।

(iii) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

(iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात आयातकों (जिनका ब्यौरा याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाया गया था) को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें पत्र के तारीख से चालीस दिनों भीतर लिखित रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

(v) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से भी अनुरोध किया गया कि वे जाँच की अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों का ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

(vi) प्राधिकारी ने नियम 6(3) के अनुसार शुरूआत अधिसूचना की प्रति ज्ञात निर्यातक तथा संबद्ध देश यूरोपियन यूनियन के दूतावास को और नई दिल्ली स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को भिजवाई।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी।

(i) मैसर्स हाल्डोर टोपोस (एचटीएस) डैनमार्क

निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर/सूचना दी गई थी।

(i) मैसर्स हाल्डोर टोपोस (एचटीएस) डैनमार्क

(viii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश यूरोपियन यूनियन के दूतावास को और नई दिल्ली स्थित यूरोपियन उच्चायोग के प्रतिनिधि मंडल को नियम 6(2) के अनुसार जाँच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गई जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के सभी संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के अंदर उत्तर देने की सलाह दें। नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रतियाँ संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थी।

(ix) संबद्ध वस्तु का निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ता परिसंघों को प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी।

निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का जवाब/के संबंध में सूचना दी गई हैं :-

(i) मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाजर्स लि० मुम्बई

(ii) मैसर्स इन्डियन ऑयल कार्पो लि० पश्चिमी बंगाल

(x) मैसर्स प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल) और मैसर्स सूब-कैमी इंडिया प्रा० लि० (ससीआईएल) जो संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं, से संबंधित सूचना मांगी गई थी। केवल मैसर्स एससीआईएल ने उत्पादन लागत/क्षति संबंधित सूचना भेजी थी। मैसर्स पीडीआईएल ने तथापि उनके विभिन्न कैंटलिस्टों के उत्पादन से संबंधित सूचना जांच अवधि के दौरान दी।

(xi) कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था जिसे प्राधिकारी द्वारा मान लिया गया था और 20.03.2002 तक अवधि बढ़ा दी गई थी। इन जांच परिणामों में इस विषय से प्राप्त टिप्पणियों को भी विधिवत मान लिया गया है।

(xii) सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा भारत में इसके विनिर्माण एवं बिक्री की लागत निकालने के लिए लागत जांच भी की गई। मैसर्स सूब-कैमी इंडिया प्रा० लि० के लागत आंकड़े भी दिए गए और उनका विश्लेषण भी किया गया।

(xiii) डेनमार्क के जवाब देने वाले एकमात्र निर्यातक मैसर्स एचटीएस से अतिरिक्त सूचना भी मांगी गई थी।

(xiv) सभी हितबद्ध पक्षकारों को 29.04.2002 को अपने मौखिक विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था। सभी पक्षकारों को अपने व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में भेजने का अनुरोध किया गया। पक्षकारों को विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और खण्डन यदि कोई है, की प्रति प्राप्त करने की सलाह दी गई थी।

(xv) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा और इसे नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा।

(xvi) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष 3.9.2002 को प्रकट किया गया।

(xvii) इस अधिसूचना में *** चिन्ह से हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती और नियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी ने इसे गोपनीय ही माना है।

(xviii) जांच अवधि 1.4.2000 से 30.9.2001 मानी गई है।

(ख). घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोक्ता संघों तथा हितबद्ध पार्टियों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच ।

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों, द्वारा दिए गए विचारों पर प्रकटन विवरण पत्र में भी विचार किया गया है । जिन विचारों पर प्रकटन विवरण-पत्र में पहले विचार नहीं किया गया है और जो अब प्रकटन विवरण-पत्र के जवाब में उठाए गए हैं, उन पर नियमों के अनुसार संगत सीमा तक और जहां तक ये इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, नीचे संगत पैराग्राफों में विचार किया गया है । कुछेक हितबद्ध पार्टियों द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा दिए गए तर्कों को प्रकटन विवरण में हिसाब से नहीं लिया गया । हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गयी, उन पर विचार किया और जहां उचित समझा गया उन पर नीचे संगत पैराग्राफों में कार्रवाई की गयी है ।

मैसर्स सूद-कैमी इंडिया प्रा० लि० (एससीआईएल) द्वारा व्यक्त किए गए विचार

(क) विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

(i) एचटीएस के संबंध में एचटीएस ने यह उल्लेख किया है कि वे विशेष कैटलिस्ट एलएस को सप्लाई कर रहे हैं । एलएस के और एलके 823 प्रकार के दोनों कैटलिस्ट बनाए जा रहे हैं और भारत में इस तरह के कैटलिस्ट नहीं बनाये जा सकते हैं । मैसर्स एचटीएस का यह दावा यह दर्शाता है कि एसटीएस भविष्य में एलटीएस कैटलिस्ट के मामले में पाटनरोधी शुल्क को घेरे में लेने के लिए भूमिका बना रहा है ।

(ii) एचटीएस कुछ संशोधनों के बाद कैटलिस्टों के प्रस्तुत करता है और उन्हें नामावली कर प्रोपराइटरी कहता है ।

(iii) मैयानेशन के संबंध में प्रिडियूस्ड कैटलिस्ट की पहचान कराने से कुछ भी क्रान्तिकारी नहीं है । घरेलू उद्योग प्रिडियूस्ड कैटलिस्ट बना सकता है अथवा परिदान से पूर्व क्रियाशील कर सकता है । एचटीएस पाटनरोधी शुल्क लगाने से एक नया प्रोपराइटरी उत्पाद की पहचान करने की व शिश कर रहा है ।

(iv) एचटीएस ने इसके मार्किट सन्सिडियरी में एचटीएस कैटलिस्ट सप्लाई किया है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमने यह अनुरोध किया है कि इस कैटलिस्ट पर यूएसए से आपूर्ति किए जाने पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए ।

(ख) पाटन**(i) सामान्य मूल्य**

(i) घरेलू उद्योग ने यूरोपियन यूनियन की सीमा के अन्दर संबद्ध कैटलिस्ट की आपूर्ति के लिए की गई जांच अवधि के दौरान मैसर्स सूद-कैमी एजी जर्मनी से प्राप्त होने वाले वास्तविक मूल्यों पर सूचना उपलब्ध कराई ।

(ii) चूंकि मैसर्स एचटीएस का कोई उपयोक्ता उद्योग नहीं है इसलिए इसका घरेलू बाजार केवल डैनमार्क तक ही सीमित नहीं है । परन्तु यूरोपियन यूनियन की समस्त सीमा में फैला हुआ है ।

(iii) मैसर्स एचटीएस ने यह माना है कि जैडएनओडीएन और एलटीएस कैटलिस्टों को भारत में पाटन स्तर के मूल्यों पर आपूर्ति किया है । जैडएनओडीएन के मामले में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं था क्योंकि प्रारंभिक जांच के दौरान घरेलू उद्योग को अपर्याप्त क्षति पहुँची जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया था कि एचटीएस के मूल्य पाटन मूल्य थे । इस दृश्य में बुरा परिवर्तन आया और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची ।

(iv) सामान्य मूल्य के लिए पाटन संगत है और उत्पादन मूल्य के लिए नहीं । सामान्य मूल्य वह मूल्य होना चाहिए जिस पर एचटीएस यूरोपियन यूनियन से कैटलिस्ट आपूर्ति करता है । मैसर्स एचटीएस द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को यूरोपियन यूनियन में यह मूल्य उपलब्ध कराने चाहिए ।

(ii) निर्यात मूल्य

(i) मैसर्स एससीआईएल ने जांच अवधि के लिए छः कैटलिस्टों पर निविदा सहभागिता ब्यौरा उपलब्ध कराया है जिसमें विभिन्न सहभागियों के लिए निविदा की सहभागिता और अवार्ड की और भी संकेत करते हैं ।

प्रकटन के उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए:-

(i) हम पुनः कहना चाहेंगे कि अंतिम समीक्षा के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और यह जांच करते हैं कि क्या मैसर्स एचटीएस पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में उत्पादों के पाटन का पुनः सहारा लेंगे ।

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस समीक्षा के अन्तर्गत जांच अवधि के सीमित समय के गठन के भीतर ही इस मामले की जांच की है। हालांकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए जांच करना पर्याप्त होगा कि वास्तविक पाठ हो रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही है जिसके लिए किसी कम्पनी के दीर्घकालिक आशयों के अनुसार कोई निष्कर्ष निकालने हेतु एक समयावधि पर्याप्त रूप से नहीं है।

(iii) हम 13 जुलाई, 2002 को किए गए अपने निवेदन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जिसमें हमने मैसर्स एचटीएस द्वारा इस समीक्षा के अन्तर्गत जांच से पूर्व पाटन के विषय में सूचना उपलब्ध कराई गई है और यह दर्शाया गया है कि मैसर्स एचटीएस, एचटीएस कैटलिस्ट के लिए अत्यधिक हानिकारक मूल्यों पर आदेश प्राप्त कर रहा है। यह अवधि जांच अवधि से अतिरिक्त थी परन्तु एचटीएस के इरादों को स्पष्ट दर्शाती है। ऐसा केवल उन आदेशों के कारण है जो एचटीएस द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं जिससे पीडीआईएल और हमें आगे आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने मूल्य कम करने पड़े। वास्तविक तथ्य है कि पीडीआईएल और हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे जैसाकि एचटीएस ने आरोप लगाया है परन्तु हम मूल्य कम करने के लिए बाध्य थे, अथवा अन्यथा एचटीएस के लिए आदेशों को छोड़ा। ऐसा नोट करना उपयुक्त होगा कि बोली के समय ऐसा सदैव मालूम नहीं होता कि दूसरे प्रतियोगी कौन हैं।

(iv) उपरोक्त (iii) में बताए गए तथ्य कों और वृहत समय गठन को ध्यान में रखते हुए हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करेंगे कि वह एचटीएस कैटलिस्ट पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखे क्योंकि पाटनरोधी शुल्क न लगाने पर एचटीएस एक बार पुनः पाटन मूल्यों पर कैटलिस्ट बैटाने का सहारा लेगा।

(v) हम अनुरोध करते हैं कि जांच अवधि के अतिरिक्त सूचना को प्रयोग करने में यदि स्वयं को असमर्थ पाते हैं, तो आप एचटीएस कैटलिस्ट के लिए स्वयं द्वारा निकाले गए अहानिकारक मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं और मैसर्स एचटीएस से यह शपथ प्राप्त कर लें कि इस प्रकार के अहानिकारक मूल्यों पर एचटीएस आपूर्ति नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कि मैसर्स उनकी हानिकारक मूल्यों पर पाटन करने की इरादा बना रहेगा, इसमें संशोधन हमारे विवाद को और मजबूत बनाने की स्थिति में होने पर मैसर्स एचटीएस ऐसा करने से इन्कार कर देगा।

(ग) क्षति एवं कारणात्मक संबंध

(i) हम अपने मार्केट शेयर को बनाए रख पा रहे हैं इसलिए हमारे उत्पादन में अथवा क्षमता उपयोगिता में और हमारे रोजगार स्तरों में कोई वास्तविक ह्रास नहीं हुआ है तथापि ऐसा हमने अपने उत्पाद में वृद्धि करने की बजाय बिक्री मूल्य में कमी करने से पाया है जिससे हमारे फायदों बहुत अधिक कमी आई है जिसका साक्षी पिछले छः वर्षों से वास्तविक स्वदेशी बिक्री में होने वाली क्षति है।

- (ii) कैटेलिस्ट-बार सूचना और पहुँच मूल्य स्पष्टतः यह संकेत करता है कि हमारे निष्पादन और पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता में एक कारणात्मक संबंध है ।
- (ii) कुछ कैटलिस्टों के मामले में पाटनरोधी शुल्क विद्यमान होने के कारण हम अपने मार्किट शेयर को बढ़ाने से और क्षमता उपयोगिता को बढ़ाने फायदा बनाए रखने में समर्थ है । तथापि, हमारे उद्योग को हुई क्षति को दूर करने में केवल यह ही पर्याप्त नहीं है जैसाकि हमारे उत्पादन के लागत की तुलना में बिक्री मूल्यों को देखने से पता चलता है ।
- (iii) मैसर्स एचटीएस की उनके कैटलिस्टों के बहुत कम मूल्य उद्धृत करने की नीति के कारण हमारे द्वारा मूल्यों में कमी करने से क्षति बनी रही ।
- (iv) जैन एनओडीएस कैटलिस्टों के मामले में एचटीएस ने पाटन करना जारी रखा तो विद्यमान शुल्क में गिरावट से पाटन मार्जिन बढ़ गया है । स्थिति अब बदल गयी है और हम जैडएनओडीएस के पाटन किए जाने से क्षति हो रही है ।
- (v) हमारे लिए क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया बहुत धीमी है । मार्किट में मूल्य वृद्धि के लिए पाटनरोधी शुल्क को प्रभावशाली बनाने के लिए पाँच वर्ष का समय बहुत कम है । इन पाँच वर्षों में से अधिकतम समय तो कानूनी प्रक्रिया में बीत गया है और मूल्य बढ़ने के मामले में कड़ा प्रतिरोध चल रहा है ।
- (vi) कैटलिस्ट के जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है और जो प्लांट डिजाइन पर निर्भर करता है । अतः पाटनरोधी शुल्क के बाजार पर प्रभावशाली होने के लिए पाँच वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है ।
- (vii) हम अपने मार्किट शेयर बनाए रख सकते हैं बशर्ते यदि पाटनरोधी शुल्क कुछ अधिक वर्षों के लिए जारी रखे जा सकें ताकि हम अपने मूल्य उस तरीके से बढ़ा सकने में समर्थ हो जिससे ग्राहक संतुष्ट हो जाए ।
- (viii) उत्पादन लागत के आधार पर 70% क्षमता उपयोगिता पर आकलित किया गया पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक बाजार क्षति की क्षतिपूर्ति करने में अपर्याप्त है ।
- (ix) मूल सीमाशुल्क 25% तक घट गया है जो निर्यातक के लिए पहुँच मूल्य के रूप में मागा गया है अब कम है जो इसके मूल्य को आगे और कम करने पर विवश कर रहा है ।
- (x) एचटीएस की रणनीति है गैर-प्रोपराइटरी कैटलिस्टों पर न्यूनतम मूल्यों को उद्धृत करना है और प्राइमरी रिफारिंग कैटलिस्ट और अमोनिया सिनपैसिस कैटलिस्टों जो उनके प्रोपराइटरी

कैटलिस्ट है, को उच्च दामो पर बेच कर उन्हें अवास्तविक फायदा पहुँचाते हुए क्षतियों की प्रतिपूर्ति करता रहा है।

(xi) मैथानेशन के मामले में जांच अवधि के दौरान कोई निविदा चालू नहीं रही थी।

(xii) सैकैन्डी रिफाइरिंग कैटलिस्ट के मामले में जांच अवधि के दौरान एक ही निविदा विज्ञापित की गई थी और आदेश एक विदेशी कम्पनी यथा मैसर्स सिन्थैटिक को ही दिया गया। एचटीएस ने इस निविदा में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था।

(xiii) एचटीएस के मामले में हमने पाया कि ऐसा विश्वास करना मुश्किल है कि एचटीएस जो अन्य कैटलिस्टों के मामले में पाटन कर रहा था ने पाटनरोधी के जारी न होने पर भी एचटीएस के पाटन को पुनः प्रारम्भ करके फायदा नहीं उठा रहा है।

(xiv) मूल्य घटाने के संबंध में एचटीएस द्वारा यह उल्लेख किया गया कि ऐसा घरेलू उत्पादकों के बीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है जैसाकि हमारे द्वारा सकेत दिया गया है कि एसटीएस के पाटन के खाते और घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त मूल्यों की वृद्धि में असमर्थता के बीच निश्चित रूप से कारणात्मक संबंध है। हम एचटीएस के विवाद से इन्कार करते हैं कि हमारी क्षति स्वप्रदत्त है।

(xv) केवल हम ही मैसर्स एचटीएस के ऐसे व्यवहार से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं परन्तु पिछले स्तरों के मुकाबले में क्षति नियमों बहुत से कारक जिम्मेदार हैं जो विद्यमान सीमाशुल्क, उत्पादन लागत, क्षमता उपयोगिता आदि जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।

2. आयातकों के विचार

राष्ट्रीय कैमिकल्स एव फर्टिलाइजर्स लि० मुम्बई और मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० मुम्बई और मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० पश्चिमी बंगाल द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं।

(क) निर्यात मूल्य

(i) विभिन्न गैर संबद्ध कैटलिस्टों के आयात मूल्य मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० मुम्बई और मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० पं० बंगाल द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जो संबद्ध कैटलिस्टों से संबंधित हैं।

3. निर्यातक का विचार

(क) मैसर्स/हैल्डर टोपसे ए/एस (एचटीएस) डेनमार्क

(क) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(i) एलटीएस पर सम्पूर्ण पाटनरोधी शुल्क के संबंध में लगाया गया आरोप गलत है क्योंकि एलटीएस कैटलिस्ट आरोधन के बाद भी पाटनरोधी शुल्क की क्षति के अधीन है। प्रोपराइटरी एलएसके और एलके 823 के साथ भारत के भीतर कोई कैटलिस्ट नहीं बनाए जा रहे हैं।

(ii) प्रि-रेडियूसड मैथानेशन कैटलिस्ट के संबंध में हमने उसे निर्यात नहीं किया है और हमने यह निवेदन किया है कि यह कैटलिस्ट भारत में आज तक विनिर्मित नहीं किया गया है।

प्रकटन सूची के जवाब में निम्नलिखित निवेदन किए गए

(i) हम प्राधिकारी के साथ सहमत हैं कि विचाराधीन उत्पाद छः कैटलिस्ट हैं जिसमें मूल जांच में पहचान की गई थी। हमने स्पष्टतः यह कहा है कि कथित कैटलिस्ट को भी पाटनरोधी शुल्क के दायरे में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वस्तुतः हमने स्पष्ट रूप से संकेत किया है कि अशोधित एलटीएस कैटलिस्ट पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। हमने केवल यह संकेत किया है कि अशोधित एलटीएस कैटलिस्ट भारत में नहीं बनाया जाता है। हम प्राधिकारी के साथ सहमत हैं कि एचडीएस कैटलिस्ट जो यूएसए से निर्यात किया गया है, मूल जांच की सीमा के भीतर नहीं था और परिणाम स्वरूप वर्तमान अंतिम समीक्षा की सीमा के भीतर नहीं है।

(ख) घरेलू उद्योग**प्रकटन के जवाब में निम्नलिखित निवेदन किए गए:-**

(i) हम निवेदन करते हैं कि एससीआईएल और पीडीआईएल घरेलू उद्योग का संघटन नहीं करते हैं। ऐसा नोट करना उपयुक्त है कि अन्तिम समीक्षा की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा की गई है और घरेलू उद्योग के अनुरोध पर नहीं। जांच प्रारंभ होने के फलस्वरूप केवल पीडीआईएल ने इस समीक्षा का समर्थन किया। अतः पीडीआईएल को घरेलू उद्योग संघटन करने में एक भाग नहीं माना जा सकता है। हमारा निवेदन इस तथ्य के द्वारा और दृढ़ होता है कि प्राधिकारी ने क्षति निर्धारण के लिए केवल एससीआईएल मूल की जांच भी की।

(ग) पाटन**(i) सामान्य मूल्य**

(i) निर्यातक ने बताया है कि समीक्षा अवधि के दौरान घरेलू बाजार में इन छः कैटलिस्टों की कोई बिक्री नहीं हुई है।

(ii) निर्यातक ने छः कैटलिस्टों के संदर्भ में अन्य देशों को किये गये निर्यात की मात्रा संबंधी जानकारी भी दी है।

(ii) निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान 6 कैटलिस्टों की उत्पादन लागत के ब्यौर दिये हैं। निर्यातक का कहना है कि 4 कैटलिस्टों का जांच अवधि के दौरान निर्यात ही नहीं हुआ

है इस निर्यात कीमत नहीं दी जा सकती अतः पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(iv) जेडएनओडीएस तथा एलटीएस कैटलिस्टों की उत्पादन लागत सूचित की गयी है और उन्हें इस कीमत पर आपूरित किया गया है जिसमें उपरी खर्चों सहित कुल लागत भी शामिल थी अतः पाटन नहीं हुआ है ।

(ii) निर्यात कीमत

मैसर्स एचटीएस ने जेडएनओडीएस तथा एलटीएस के एफओबी मूल्य और समुद्री भाड़े तथा पूर्व-एफओबी खर्चों के बारे में जानकारी दी है ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने निम्नलिखित निवेदन किये हैं :

(i) हम प्राधिकारी के इस तर्क से सहमत हैं कि मेथानेशन, सैकेण्डरी रिफोर्मिंग, एचडीएस तथा एचटीएस कैटलिस्टों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये चार कैटलिस्ट समीक्षा अवधि के दौरान निर्यात नहीं किये गये हैं । इसके अलावा एचटीएस ने संबद्ध कैटलिस्टों में से दो के लिए निविदा प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया है । मामला जो भी हो निर्यात कीमत न होने के कारण पाटन मार्जिन का निर्धारण असंभव है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि समीक्षा अवधि के दौरान इन चार कैटलिस्टों का पाटन किया गया है । इन चार कैटलिस्टों के पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना भी बहुत ही कम है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह ठीक ही कहा है कि क्योंकि एचटीएस ने समीक्षा अवधि के दौरान निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है । इन कैटलिस्टों के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं किये हैं ।

(ii) हम इस बात पर पुनः बल देते हैं कि मूल जांच यूरोपीय संघ के खिलाफ न हो कर केवल डेनमार्क के खिलाफ थी । अतः जांच समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ को घरेलू बाजार मानना गैर-काजूनी और गलत है । अतः एचटीएस अपने पहले वाले निवेदन को दोहराती है कि सामान्य मूल्य (अन्य दो कैटलिस्टों हेतु) का निर्धारण परिगठित मूल्य (उत्पादन लागत जमा लाभ) के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(.ii) एचटीएस ने नोट किया कि प्राधिकारी ने LTS और जेडएनओडीएस कैटलिस्टों का सामान्य मूल्य जर्मनी में घरेलू विक्रय मूल्य के आधार पर किया है जो SCIL द्वारा उपलब्ध कराए गये थे । HTAS ने मात्र 60,400 लीटर LTS कैटलिस्ट और 87,200 लीटर जिक ऑक्साइड कैटलिस्ट का निर्यात किया था । LTS कैटलिस्ट के लिए केवल दो और जिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के लिए 7 लेनदेन हुए थे । यह ज्ञात नहीं है कि क्या SCIL ने जांच के 18 महीनों में पूरे यूरोपीय संघ में इन दो कैटलिस्टों की बिक्री के ब्यौरे दिये थे । हमारा यह निवेदन है कि SCIL ने संभवतः जर्मनी में ऊंची कीमतों पर केवल कुछ बिक्री मामलों की चुनिंदा जानकारी दी है ताकि पाटन मार्जिन को विकृत किया जा सकें । घरेलू उद्योग द्वारा जर्मनी स्थित अपने सहयोगियों जो जानकारी एकत्र की गयी है उसे सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु प्रयोग किया जा

रहा है। अतः इसे केवल वैधीकरण के बाद ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी का ध्यान हम सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी संबंधी अनुच्छेद- vi के कार्यान्वयन समझौते के अनुबंध-11 के पैरा-7 की ओर दिलाना चाहते हैं। जर्मनी में अपने सहयोगी से सूचना प्राप्त कर सकने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उस जानकारी का चुन कर उपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उनकी जानकारी को पूरी तरह मान्य किया जाना चाहिए।

(iv) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार जिक ऑक्साइड कैटलिस्ट समीक्षा अवधि के दौरान यूरोप में नहीं बेचा गया था। इस संबंध में हम प्राधिकारी से SCIL के दावे का सत्यापन करने का अनुरोध करते हैं। हम समझते हैं कि LTS कैटलिस्ट के लिए केवल एक छोटा सा क्रयादेश 10,000 लीटर का था। ऐसा जान पड़ता है कि इस मात्रा के लिए कीमत सूद-केमी से मोलभाव करके तय की गयी होगी। हमारा निवेदन यह है कि LTS कैटलिस्ट के लिए कीमत सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों वाली नहीं है क्योंकि यह एकल स्रोत आपूर्ति थी, प्रतिस्पर्धी स्थितियों में नहीं। अतः उक्त कीमत को LTS कैटलिस्ट का सामान्य मूल्य तय करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ख) यूरोपियन आयोग, यूरोपियन आयाग का शिष्टमंडल, नई दिल्ली

(क) पाटन

यूरोपियन संघ, यूरोपियन आयोग के शिष्टमंडल, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया गया है:-

(i) पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए शिकायतकर्ता के एक जर्मनी स्थित सहयोगी की सूची कीमतों का उपयोग करके निर्दिष्ट प्राधिकारी ने WTO पाटन-रोधी समझौते के अनुच्छेद-2.2 का उल्लंघन किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित तीसरे देश निर्यात किये जाने पर समान वस्तु की समतुल्य कीमत तुलना करके किया जा सकता है, बशर्ते कि यह कीमत प्रतिनिधि कीमत हो। चूंकि सूची कीमतें निर्यातक कम्पनी की नहीं थी - डेनमार्क (यूरोपीय संघ निर्यातक क्षेत्र नहीं हो सकता क्योंकि WTO पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 12.1 के अनुसार यूरोपीय आयोग को जांच की सूचना कभी नहीं दी गयी थी) और सूची मूल्य भी "समतुल्य" नहीं थे क्योंकि डैनिश निर्यातक HTAS ने यह दर्शाने के सबूत पेश किये हैं कि सूद-केमी की वास्तविक कीमतें इसके सूची मूल्यों की तुलना में 30% से 52% के बीच कम थीं।

(ii) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्राधिकृत भी थे कि डैनिश निर्यातक ने कोई सूचना देने से इंकार किया है तब भी उन्हें निर्यातक की लागत संबंधी सूचना की अतमानना नहीं करनी चाहिये थी। सूचना अस्वीकार करने के कारणों का खुलासा न करके और शिकायतकर्ता की प्रयुक्त सूचना के प्रमाणक मूल्य ठीक से सत्यापन नहीं करके, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने WTO पाटनरोधी समझौते के अनुबंध-11 और अनुच्छेद 6.8 का उल्लंघन किया है।

(iii) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की परिगणना करने तथा अभिकलित क्षति का निर्धारण करने के प्रयोग की गयी महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी डैनिश निर्यात को न देकर WTO पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद-6.2 और 6.4 का उल्लंघन किया है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किये गये हैं:-

(i) WTO पाटनरोधी समझौते (एडीए) के अनुच्छेद-11 (3) में यह अपेक्षा की गयी है कि -
 '..... एक समीक्षा द्वारा यदि प्राधिकारी यह तय नहीं कर लेते कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तब कोई भी पाटनरोधी शुल्क इसके लागू की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाएगा

इसमें समीक्षाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व की अपेक्षा रखने का प्रावधान है। किन्तु कैटलिस्ट जेडएनओडीएस के मामले में ये नहीं था। अतः जो शुल्क विद्यमान ही नहीं है वह शुल्क इस उत्पाद पर उंची दर से लगाने को न्यायोचित ठहराने के लिए, शुल्क समाप्ति के आधार पर जारी रहने और पुनरावृत्ति होने की जांच का उपयोग करना संभव ही नहीं है। निश्चय ही इस उत्पाद को इस समीक्षा में शामिल करने पर अनेक सवाल किये जा सकते हैं।

यूरोपीय आयोग का कहना है कि भारत केवल जेडएनओडीएस पर ही पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद-5 के अधीन पूरी-विस्तृत जांच के बाद ही शुल्क लगा सकता है।

(ii) सामान्य मूल्य की गणना WTO पाटनरोधी समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। समझौते में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब घरेलू बिक्री बिल्कुल न हो तब प्राधिकारी को निश्चित रूप से या तो 'उचित तीसरे देश को निर्यात होने पर उत्पाद के समान वस्तु तुलनीय कीमत, अथवाउद्गम के देश में उत्पाद लागत' को ही प्रयोग करना चाहिये।

भारतीय प्राधिकारियों यूरोपीय संघ को घरेलू बाजार के रूप माना है और कहा है कि घरेलू बाजार में इसकी कोई बिक्री नहीं है। किन्तु तब जर्मनी के घरेलू उत्पादक को सूची मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना का कार्य आरंभ कर दिया। यदि यह माना जाता है कि बाजार में घरेलू बिक्री नहीं है तो प्राधिकारियों को तीसरे देश को निर्यात मूल्य अथवा WTO समझौते के अनुसार उत्पादन लागत का ही सहारा लेना चाहिए था। संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के बारे में डैनिश नियतक द्वारा पूरी सूचना दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने यह नहीं किया। कुछ भी हो, यह तो उल्लेख करना ही चाहिए कि जर्मनी के घरेलू उत्पादक के सूची मूल्यों में डिस्काउंट तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण समायोजनों का हिसाब नहीं है जो उत्पाद की वास्तविक बिक्री के समय होते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये कीमतें प्रतिस्थापना हेतु है अथवा नये उपकरण के लिए, यह एक ऐसा तथ्य है जो बहुत ही सुसंगत है और भारत इसपर कोई निष्कर्ष नहीं रहा।

(घ) क्षति और कारणात्मक संबंध(क) मै0 हैल्डोर ट्रॉप्सोए ए/एस (HTAS) , डेनमार्क

(i) जाच अवधि के दौरान मैसर्स HTAS 4 कैटलिस्टो का कोई भी क्रयादेश प्राप्त करने में असमर्थ रहा क्योंकि विवाद के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी और इस दौरान निविदाओं का मूल्यांकन करते समय और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू हो जाने के बाद ग्राहक यही मानकर हिसाब लगाते रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू हो गया है।

(ii) यह तर्क कि मैसर्स सूद-केमी अनिश्चितता के कारण कोई मूल्य वृद्धि नहीं कर सकता, ठीक तस्वीर नहीं पेश करता।

(iii) मै0 सूद-केमी का यह निवेदन कि वे विनाशक कीमतों को बाजार भाव पर रोकने या बढ़ाने में असमर्थ रहे, यह भी कोटेशन देते समय उनके अपने अनुमानों का परिणाम है। यदि कोई क्षति हुई है तो वे इन विनाशक मूल्यों पर क्रयादेश लेने के कारण हैं जो उन्हीं की उत्पन्न की हुई पीछा है और इसके लिए पाटन को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

(iv) जहां तक अहानिकर कीमत का संबंध है, इष्टतम क्षमता उपयोग पर अहानिकर मूल्य निर्धारण करने हेतु एक अवधि में 70% के क्षमता उपयोग के आधार पर अपनायी जाने वाली यह एक सुसंगत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सभी मामलों में अपनायी गयी है।

(v) मैसर्स सूद-केमी को होने वाली क्षति, पाटनरोधी शुल्क लग जाने के बावजूद कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन लागत ऊंची होने के कारण जो इसी बात का समर्थन करती है कि क्षति का कारण पाटन से पूर्णतया असंबद्ध है।

(vi) सीमाशुल्क में कमी एक नियमित घटना है और यह कहना अनुचित है कि निर्यातों ने कीमतों को इतना गिरा दिया है कि सीमाशुल्क में कमी हो गयी। इस अवधि के दौरान HTAS एक भी क्रयादेश प्राप्त नहीं कर सका एक ऐसा तथ्य है जो यह बताता है कि सीमाशुल्क में कमी से निर्यातकों को कोई लाभ नहीं मिला है।

(vii) मैसर्स सूद-केमी द्वारा उल्लिखित प्रोपराइटी कैटलिस्ट के संबंध में उल्लेखनीय है कि टेक्नोलाजी देने वालों के यह एक सामान्य प्रथा है कि कुछ विशिष्ट पूर्व-शर्तें रखी जाएं जैसे कि डिजाइन मानदंड, आपूरित कैटलिस्ट सहित हार्डवेयर ताकि संयंत्र के कार्य निष्पादन की गारंटी पर टिका जा सके। ये कैटलिस्ट वे नहीं हैं जिनकी जांच चल रही है, अतः इनका उल्लेख अप्रासंगिक है।

(viii) मैसर्स PDIL को घरेलू उद्योग में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण पहले वाली जांच में हानि का मार्जिन अधिक था। क्योंकि वर्तमान जांच में PDIL ने सहयोग नहीं किया है इसलिए अहानिकर मूल्य का निर्धारण केवल मै0 सूद-केमी की उत्पादन लागत के आधार पर ही

होगा और तब कोई क्षति मार्जिन नहीं होगा । अतः कोई क्षति जारी नहीं है और ना ही क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

(ix) अंतिम समीक्षा या समापन समीक्षा में प्राधिकारियों को निम्नलिखित दो पहलुओं का मूल्यांकन करना होगा:-

(क) क्या पाटन और क्षति जारी है ।

(ख) क्या शुल्क हटालेने से पाटन और क्षति पुनः होने की संभावना है समीक्षा अवधि के दौरान HTAS ने "लो टेपरेचर शिफ्ट कैटलिस्ट" की दो खेप आपूरित की थीं । इस कैटलिस्ट की एक किस्म नहीं थी जो मैथेनोल बनाने की दर कम थी । यह कैटलिस्ट भारत में नहीं बनाया जा रहा है । अतः जो कैटलिस्ट भारत में नहीं बन रहा उसके निर्यात से घरेलू उत्पादक को वास्तविक हानि नहीं हो सकती ।

इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया जाता है कि मूल जांच में PDIL और SCIL नामक दो घरेलू उत्पादक थे । वर्तमान जांच में, जो प्राधिकारी ने स्वयं अपनी ओर से आरंभ की है, PDIL ने कोई सहयोग नहीं दिया है । SCIL की एकमात्र घरेलू उत्पादक है जिसकी क्षति पुनरावृत्ति का विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा किया जाना है । निवेदन है कि PDIL का सहयोग न करना एक महत्वपूर्ण बात है और केवल SCIL को पुनः होने वाली क्षति का ही मूल्यांकन न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना है । क्योंकि पाटन और क्षति का आधार कोरी कल्पना या क्षीण संभावना नहीं होगा इसलिये PDIL ने सहयोग न करने का विकल्प चुना है । अतः प्राधिकारी पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति पर नकारात्मक फैसला दे सकते हैं ।

(x) यह नोट किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि SCIL ने समापन समीक्षा आरंभ करने के अनुरोध के साथ प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया है । अब क्योंकि प्राधिकारी ने समीक्षा शुरू कर दी है तो वह भी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं । यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो क्षति के जारी रहने या पुनः होने की क्षीण संभावना को दर्शाता है ।

(xi) हम निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में एस सी आई एल की यह बात भी लाना चाहते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि में क्रमादेश या तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए थे अथवा पी डी आई एल द्वारा और पाटनरोधी शुल्क लागू हो जाने से कीमतों में खास बदलाव नहीं आया था। इस बात से स्पष्ट सुझाव मिलता है कि घरेलू बाजार की प्रचलित कीमतें आंतरिक प्रतियोगिता से निर्धारित होती हैं और उन पर एच टी ए एस की कीमतों यदि इन कीमतों के कारण, जो कि समीक्षा अवधि के दौरान प्रचलित थीं; एस सी आई एल घाटा (क्षति) हुआ है तो उसका कारणात्मक संबंध एस टी ए एस से नहीं जोड़ा जा सकता। अतः क्षति की पुनरावृत्ति फिर कोरी कल्पना है। यदि कोई क्षति है वह आत्म प्रहार के कारण है और उसे वास्तविक क्षति का जारी रहना अथवा वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति नहीं माना जा सकता जिसके लिए पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी जरूरी माना जाता है।

(xii) प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान एस सी आई एल से उन निविदाओं की संख्या के बारे में जो वे हार गए थे और क्या उन्होंने वे निविदाओं घरेलू उद्योग के कारण हारी थी संबंधी प्रश्नों से हम पूर्णतया सहमत हैं। क्योंकि आरोपित पाटन विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के द्वारा ठीक हो गया था, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा इस अवसर का लाभ न उठा सकना यही दर्शाता है कि यदि उन्हें कोई क्षति हुई थी तो वह किसी भी प्रकार आरोपित पाटन के कारण नहीं हुई थी। वास्तव में, हमारे इस निवेदन को सीधा बल देता है कि यदि कोई क्षति हुई है तो वह एस टी ए एस के कारण बिल्कुल नहीं हुई है।

प्रकटन के उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

- (i) दो कैटलिस्टों के लिए प्रति लिटर और प्रति किग्रा सी आई एफ मूल्य डालरों में नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

कैटलिस्ट	एफ ओ बी मूल्य \$	समुद्री भाड़ा \$	समुद्री बीमा \$	सी आई एफ \$
जिक आक्साइड	3.162/ लिटर	0.07	0.005	3.237
एल टी एस	5.12/लिटर	0.07	0.008	5.198

- (ii) हम प्राधिका से पहुंच मूल्य निर्धारित करने और यह जांच करने के लिए कि क्या क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कम है के लिए उपर्युक्त सी आई एफ मूल्यों का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं।
- (iii) प्रकटन विवरण में एस सी आई एल यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल और एस टी ए एस के निवेदनों से ही दोहराया गया है। पैरा 4 प्राधिकारी द्वारा जांच से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए इन निवेदनों पर विचार किया जाएगा। अन्य शब्दों में क्षति के अस्तित्व या पुनरावृत्ति के बारे में कोई प्रकटन नहीं है। प्रकटन विवरण दोषपूर्ण है।
- (iv) प्राधिकारी को याद होगा कि एच टी ए एस ने मूल जांच में यह इंगित किया था कि छः कैटलिस्टों में प्रत्येक एक भिन्न समान उत्पाद था। कैटलिस्टों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता अतः छः कैटलिस्टों में से प्रत्येक के लिए क्षति निर्धारण अलग अलग होना चाहिए। प्राधिकारी ने इस अवधारण को स्वीकार नहीं किया था और सभी कैटलिस्टों को एक

साथ मिला कर सचयी रूप से क्षति का निर्धारण किया था तथा पाटनरोधी समझौते अनुच्छेद 3.6 का उल्लंघन किया था। वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध कैटलिस्टों में 4 का निर्यात ही नहीं हुआ है। जिक्र ऑक्साइड कैटलिस्ट को जांच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि मूल जांच में उक्त कैटलिस्ट पर शुल्क शून्य था। क्योंकि जिक्र आक्साइड कैटलिस्ट पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा हुआ था इसलिए इसे वर्तमान समीक्षा का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। धारा 9क(5)के प्रावधान समीक्षा के आधार वाक्य के रूप में यह व्यवस्था है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्त होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। शुल्क हटाने के पूर्व धारणा है कि पाटनरोधी शुल्क विद्यमान है। जिक्र आक्साइड कैटलिस्ट पर कोई शुल्क था ही नहीं इसलिए जिक्र आक्साइड कैटलिस्ट पर से शुल्क हटाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अंतिम समीक्षा में जिक्र आक्साइड को शामिल करना गलत है।

- (v) अतः क्षति विश्लेषण एल टी एस कैटलिस्ट तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसकि प्राधिकारी ने पहले कहा था कि प्रत्येक कैटलिस्ट की क्षति का निर्धारण अलग अलग किया जाना संभव नहीं है, यदि सभी छः कैटलिस्टों को क्षति निर्धारण एक ही प्रकार के मानदंडों से किया जाएगा तो इससे क्षति निर्धारण पूरी तरह खराब हो जाएगा तो इससे क्षति निर्धारण पूरी तरह खराब हो जाएगा। अतः प्राधिकारी एल टी एस जिक्र आक्साइड कैटलिस्ट की क्षति के अस्तित्व अथवा उसकी पुनरावृत्ति का निर्धारण नहीं कर सकते। परिणामतः समीक्षा की परिणति सभी कैटलिस्टों पर शुल्क की समाप्ति में होनी चाहिए।
- (vi) उपर्युक्त पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना हम प्राधिकारी की इस बात से पूर्णतया समह है कि चार कैटलिस्टों पर पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पुनः क्षति नहीं होगी। एस सी आइ एल ने तर्क दिया है कि उन्हें समीक्षा अवधि में क्षति पहुंची है और यह क्षति पाटन के कारण हुई है। उनके अपने कथन से ही यह स्पष्ट है कि किसी भी मूल्य वृद्धि के मामले में उन्हें ग्राहकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। यह पूर्णतया एक वाणिज्यिक पहलू है और इसके लिए एच टी ए एस को जिम्मेदार नहीं उहाराया जा सकता क्योंकि इसने तो इनमें से चार कैटलिस्ट आपूर्ति ही नहीं किए है।
- (vii) यह कहना कि सीमाशुल्क घटने से पाटन मार्जिन बढ़ा है बिल्कुल गलत है। पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से तय होता है जो किसी भी प्रकार भारत में विद्यमान सीमाशुल्क पर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार गैर प्रोपराइटी कैटलिस्टों की कीमत कम और प्रोपराइटी कैटलिस्टों का कीमत अधिक होने के बारे में उनका तर्क इस मामले में बिल्कुल अप्रासंगिक है और इसका कोई आधार या सबूत नहीं है। अंतिम शुल्क जून 1997 में लगाया गया था और यह अब तक चालू है। इस परिप्रेक्ष्य में एस सी आइ एल का यह तर्क समझना कठिन है कि 1997 से 2002 के बीच हुई आरोपित क्षति एच टी ए एस द्वारा हुई है। यदि एस सी आइ एल को यह क्षति तब हुई है जबकि इनमें से चार कैटलिस्ट निर्यात ही नहीं किए गए तो इसका एक मात्र अर्थ यही है कि ये क्षति आत्मघात के कारण ही हुई है। वास्तव में एस सी आइ ने माना है कि क्षति सीमाशुल्क में कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि आदि के कारण हुई है। ये ही परिशुद्ध कारण है जिन का विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या वास्तविक क्षति पाटनेतर कारणों से हुई है। वास्तव में केवल चार कैटलिस्टों पर से पाटनरोधी हटाने की बजाए इस जांच को ही पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (viii) उपर्युक्त को देखते हुए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि क्षति और कारणात्मक संबंध विश्लेषण के समग्र पहलू की पुनः जांच की जाए और संशोधित प्रकटन जारी किया जाए। हमारा

यह निवेदन है कि दो कैटलिस्टों के निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। अतः न तो वास्तविक क्षति विद्यमान है और न ही वास्तविक क्षति दुबारा होने की संभावना है।

- (ix) हम माननीय प्राधिकारी से अंतिम समीक्षा समाप्त करने और सभी छः कैटलिस्टों पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।

(ख) यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ का शिष्टमंडल, नई दिल्ली

- (i) डब्लू टी ओ पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 3.4 के अधीन यथा निर्धारित घरेलू उद्योग की स्थिति संबंधी सभी कारकों का विश्लेषण न करके प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया है।
- (ii) आरोपित पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध न दिखा कर और घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अन्य संभव कारणों की जांच में असफल रह कर प्राधिकारी ने डब्लू टी ओ पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 3.5 का उल्लंघन किया है।

प्रकटन के उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:

- i) यूरोपीय आयोग ने इस मामले क्षति विश्लेषण को अनेक मुद्दों पर बहुत कमजोर पाया है:-
- जिनमें क्षति पायी गयी थी उनमें से दो उत्पादों, कैटलिस्ट जेड एन ओ डी एस को उपर्युक्त i) में दिए गए कारणों से विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
 - डैनिश निर्यातक के तर्क के बावजूद भारतीय प्राधिकारियों ने सभी छः कैटलिस्टों को समान वस्तु परिभाषित किया है। समीक्षा जांच में क्षति संबंधी निष्कर्षों से अब यह प्रतीत होता है कि जांच प्राधिकारी ने समान वस्तु का परिभाषा स्पष्टता स्वीकार किए बिना दुबारा की है। हमारी ओर से इस धारणा कारण यह है कि क्षति विश्लेषण के दौरान छः में से चार उत्पादों के संबंध में क्षति नहीं पायी गई जिसका अर्थ है कि क्षति विश्लेषण के लिए तरीके अलग अलग होने चाहिए।
 - ये निष्कर्ष मूल निष्कर्षों का विरोधामासा देते हैं कि ये कैटलिस्ट समान वस्तु है और डब्लू टी ओ नियमावली यह स्पष्ट कहती है समान वस्तु के लिए क्षति निर्धारण समग्रतः होना चाहिए। इससे यह प्रश्न उठता है कि जब दो तिहाई अक्षति कर , पाए गए थे तो शेष एक तिहाई क्षतिकर कैसे हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में क्षति का अस्तित्व तभी माना जा सकता है जब गहन क्षति और कारण विश्लेषण का यह परिणाम निकले कि संबंधित दो मांडलों यदि जी एन डी एस को छोड़कर दिया जा ए जो वास्तव में केवल एक) द्वारा हुई आरोपित क्षति समग्र उत्पाद रेंज के संदर्भ में थी। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।
 - यूरोपीय आयोग को प्रकटन कागजातों और डैनिश निर्यातक से प्राप्त जानकारी के संदर्भ में एक बात और कहनी है। निर्यातक ने बताया है कि वास्तव में भारत को इसके निर्यात की कीमत इसकी उत्पादन लागत से अधिक है अतः वे घाटा देने वाली नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि भारती अहानिकर कीमत पर पहुंच ने के लिए उसमें जो भी जोड़ा जाएगा वह डैनिश उत्पादक के मुकाबले भारती घरेलू उत्पादक की अकुशलता की मात्रा का परिचायक होगा। मूल जांच में यह 88% से 266% तक था। भारतीय घरेलू उत्पादकों द्वारा डैनिश निर्यातक की उत्पादन लागत से इतना अधिक अहानिकर कीमत

की अपेक्षा करता है कि यह विश्वास करना ही कठिन हो जाता है उनको हुई क्षति में अन्य कारकों कोई हाथ ही नहीं है।

अतः संक्षेप में यूरोपीय आयोग का विचार है कि जांच में अंतिम समीक्षा संबंधी डब्लू टी ओ समझौते के अनुच्छेद 11 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। प्रस्तुत सबूत हालांकि छोटे हैं, यह बताते हैं कि कैटलिस्ट संबंधी पाटन रोधी कार्यवाही अब बंद कर दी जानी चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

जहां तक नियमानुसार प्रासंगिक है और इस मामले से संबंध रखते, उपर्युक्त विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों का जांच की गई है उन पर विचार किया गया है और इन जांच परिणामों उचित स्थान पर उन पर चर्चा भी की गई है।

1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद अर्थात् कैटलिस्ट नामतः हाइड्रोडी सल्फ्यूराइजेन (एच डी एस), जिक औक्साइड डीसल्फ्यूराइजेन (जेड एन ओ डी एस) हाइ टेम्पचर शिफ्ट (एच टी एस) लोटेम्पचर शिफ्ट (एल टी एस) सेकण्डरी रिफॉर्निंग (एस आर) और मिथानेशन कैटलिस्ट (मिथ) संबंधी समीक्षा जांच है जैसा कि दिनांक 7 मई 1997 अनंतिम जांच परिणामों और 5 जनवरी 1998 के अंतिम जांच परिणामों में भी बताया गया है जिसे इसके बाद मूल जांच कहा गया है। और जिसकी सिफारिशें सीमाशुल्क अधिसूचना सं. क्रमशः 56 दिनांक 20/6/97 और 2 दिनांक 2.2.98 द्वारा लागू की गई थी। इन कैटलिस्टों के तकनीकी विवरण के ब्यौरे मूल जांच और संबंधी सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में दिए गए हैं। संबद्ध कैटलिस्ट कस्टम टैरिफ वर्गीकरण 38.15 के अधीन वर्गीकृत है और इन की निकासी प्रोजेक्ट आयात के रूप में अध्याय 98 के अधीन भी होती है। क्योंकि वर्तमान जांच 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(5) अधीन एक समीक्षा है इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का प्रभाव क्षेत्र केवल मूल जांच तक ही सीमित रहेगा जैसकि ऊपर बताया जा चुका है।

प्राधिकारी ने एल टी एस कैटलिस्ट को विभिन्न नामावलियों में लपेटने और एच डी एस कैटलिस्ट की आपूर्ति अमेरिका द्वारा विभिन्न रूपों में किए जाने के बारे में एस सी आई एल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए यह माना है कि विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विवरण दिनांक 7.7.1997 की अनंतिम जांच के परिणामों के पैरा 3(5) से 3(9) में मूल जांच के दौरान स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं और जो भी उत्पाद इन तकनीकों विवरणों के अनुरूप होगा वह विचाराधीन उत्पाद के प्रभाव क्षेत्र में आयेगा चाहे उसका व्यापारिक नाम कुछ भी हो। अमेरिका से निर्यात हाने वाले कैटलिस्ट के संबंध में उल्लेख है यह वर्तमान समापन समीक्षा के अधीन नहीं आता है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद संबंधी जांच परिणामों को पुन दोहराते हैं जिनका उल्लेख 7 मई 1997 के प्राथमिक जांच परिणामों के पैरा ड(5) से ड(8) में और 5 जनवरी 1998 के अंतिम जांच परिणामों के पैरा ड(5) में किया गया है।

घरेलू उद्योग

प्राधिकारी यह मानते हैं कि मूल जांच में मै. युनाइटेड कैटलिस्ट इंडिया लि. (यू सी आइ एल) अब मै. सूद के मी इंडिया प्रा.लि. (एस सी आइ एल) और मै. प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पी डी आइ एल) ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था। वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि मै. एच टी ए एस ने यह उल्लेख किया है कि यह जांच अपनी ओर ले आरंभ की गई समीक्षा है और मै. पी डी आइ एल द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है तथा केवल मै. एस सी आइ एल को ही घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. पी डी आइ एल ने जांच अवधि के दौरान विभिन्न संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी है और जांच अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पाद में मै. एस सी आइ एल के हिस्से को देखते पाटनरोधी नियम 2(ख) के अनुसार वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

(i) जैड एन ओ डी एस और एन टी एस कैटलिस्टों के लिए

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षधरों द्वारा किए गए निवेदन और मै. हाल्डोर टोपसाई एच टी ए एस द्वारा भेजे गए जबाब ये दर्शाते हैं कि जांच अवधि के दौरान केवल दो कैटलिस्टों अर्थात् जिक मासाझा डिस्ट्रिब्यूटराजेशन (जैड एन ओ डी एस) और लो टैम्प्रेयक शिल्ट (एल टी एस) का ही निर्यात हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं सभी छः कैटलिस्टों के संबंध में निर्यातक यह संकेत करते हैं कि इनकी डेनमार्क में कोई बिक्री नहीं हो रही और भारत को निर्यात होने वाले केवल दो कैटलिस्टों के लिए उत्पादन लागत उपलब्ध कराई है और वे पाटित मूल्य पर नहीं है। प्राधिकारी यूरोपीयन यूनियन, यूरोपीयन उच्चायोग नई दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए निवेदनों के संबंध में तो यह नोट करते हैं जिसमें यह निर्दिष्ट है कि मूल जांच में दी गई मूल्य सूची जिसका हवाला प्राधिकारी द्वारा दिया गया है। तुलनीय नहीं है क्योंकि डेनमार्क के निर्यातक मै. एच टी ए एस ने इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि मै. सूद कैमी का निर्यात मूल्य 30% और 52% के बीच में ये जोकि मूल्य सूची से कम थे यूरोपीयन यूनियन और यूरोपीयन उच्चायोग नई दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल ने यह निवेदन किए हैं कि प्राधिकारी निर्यातक की उत्पाद मूल्य संबंधी सूचना की उपेक्षा न करे और इन सूचनाओं की अपेक्षा किए जाने की वजह से प्राधिकारी ने डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 का उल्लंघन किया है। प्राधिकारी प्रकटन के जबाब में यह नोट करते हैं कि ऐसा उल्लेख किया गया है कि मै. एस सी आइ एल द्वारा दी गई सूचना चयनात्मक है और जांच अवधि के दौरान जैड एन ओ डी एस कैटलिस्ट के ई यू क्षेत्र में बिक्री नहीं की गई थी और एल टी एस कैटलिस्ट की बिक्री सामान्य व्यापार के दौरान नहीं की गई थी।

प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यूरोपीय संघ के क्षेत्र में घरेलू बिक्री न होने की जो स्थिति मूल जांच अवधि में विद्यमान थी वही परिस्थिति इस समीक्षा अवधि के दौरान भी विद्यमान है। किन्तु प्राधिकारी को मै. सूद कैमी ए जी, जर्मनी द्वारा जर्मनी में की गयी घरेलू बिक्री के विक्रय मूल्य संबंधी जानकारी साक्ष्य मिली है। ये घरेलू विक्रय मूल्य जांच अवधि के दौरान दो कैटलिस्टों की बिक्री के हैं और इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारणार्थ इन्हें प्रतिनिधि घरेलू बिक्री मूल्य माना जा सकता है क्योंकि मै. एच टी ए एस

की जानकारी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने 20.7.2000 के निर्णय में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य गणना हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति को उचित माना है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार, जिसे निर्यातक ने चुनौती भी नहीं दी थी, उचित संदर्भ और सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु निर्यातक द्वारा उस घरेलू बिक्री संबंधी मूल्यों की जानकारी प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी जो जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ क्षेत्र में हुई थी। किन्तु निर्यातक ने वही स्थिति बनाए रखी जो उसने मूल जांच के दौरान अपनायी थी और यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल ने भी वही तर्क दिए। यद्यपि प्रकटन के उत्तर में मै. एस टी. ए एस और यू. सं. ने सामान्य मूल्य परिगणना के बारे में अपने विचार तो दिए हैं किन्तु अपने दावे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, जबकि सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को समुचित साक्ष्य दिए हैं। यूरोपीय संघ क्षेत्र में घरेलू विक्रय मूल्यों की जानकारी केवल मै. एस सी आइ एल द्वारा मात्र दो कैटलिस्टों हेतु ही दी गई है, इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने इन दो कैटलिस्टों के सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए ही इस जानकारी को संदर्भित किया है।

प्राधिकारी का मानना है कि यदि मै. एस सी आइ एल द्वारा उपलब्ध करायी गई मै. सूद केमी ए जी जर्मनी के घरेलू विक्रय मूल्यों पर यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल के कथनानुसार 52% की अधिकतम कटौती भी की जाए तब भी इन दो कैटलिस्टों के संदर्भ में निश्चयात्मक पाटन मार्जिन देखने में आता है। किन्तु यूरोपीय संघ क्षेत्र में या तीसरे देश में निर्यातक द्वारा अपने घरेलू विक्रय मूल्य की कोई निश्चयात्मक सूचना दी है और न ही प्रकटन विवरण के उत्तर में यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल द्वारा यथा निवेदित सूची मूल्यों पर 30% से 52% तक की कटौती के बारे में किसी प्रकार की सूचना दी है। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जाने वाला तरीका दिनांक 5.1.1998 की मूल जांच परिणामों के पैरा च(6) के अनुसार अनुकूल है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था और निर्यातक ने उसे चुनौती भी नहीं दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ग), पाटनरोधी निर्यातवली के अनुबंध-1 को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु निर्यात द्वारा दिए गए उक्त दान लाभ ब्यौरों का संदर्भ लेना उचित नहीं समझा वरन् उस सूचना को अपनाया जो मै. एस सी आइ एल द्वारा सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु उपलब्ध करायी गई थी और जो मूल जांच के अनुरूप है।

जेड एन ओ डी एस तथा एल टी एस का सामान्य मूल्य क्रमशः ***/किग्रा और ***/किग्रा है।

(ii) अन्य कैटलिस्ट अर्थात् हाइड्रोडीसल्फाइजेशन (एचडीएस, हाइ टेम्प्रेचर शिफ्ट(एचटीएस) सैकेन्डरी रिफॉर्निंग (एस आर) और मेथानेशन(मेथ))

उपर्युक्त चार कैटलिस्टों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एस टी ए एस द्वारा जांच अवधि के दौरान और उससे पहले के दो वर्षों के दौरान भी कोई निर्यात नहीं किया गया और मेथानेशन और सैकेन्डरी रिफॉर्निंग कैटलिस्टों के लिए भारत को निर्यात हेतु निविदा प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया है। हाइ टेम्प्रेचर शिफ्ट कैटलिस्ट के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स एस सी आइ एल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, मूल्य कटान और संकुचन की घटना अन्य घरेलू उत्पादकों से स्पर्धा के कारण हुई है, अतः ऐसा नहीं लगता कि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने से क्षति और पाटन की पुनरावृत्ति

होगी। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि यह निर्णय नहीं निकाला जा सकता कि इन परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होगी अतः इन कैटलिस्टों के बारे में सामान्य मूल्य निर्धारण करना उचित नहीं समझे। हाइड्रोडीस्फराइजेशन कैटलिस्ट के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य निर्यातकों ने भी भाग लिया है और मै. एच टी ए एस को अनुपस्थिति मै. उन्हें क्रमादेश भी मिले हैं, जांच अवधि के दौरान मै. एच टी ए एस कोई क्रमादेश प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ तो इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता शुल्क समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकारी इस कैटलिस्ट के लिए भी सामान्य मूल्य के निर्धारण को उपयुक्त नहीं मानते हैं। अन्य दो कैटलिस्टों यथा मैथानेशन और सैकेन्डी रिफार्निंग का संबंध है जैसाकि मैसर्स एच टी ए एस ने जांच अवधि के दौरान भारत में निर्यातों के लिए विवाद माले में ऐसा दिखाई नहीं देना है जहां पाटनरोधी शुल्क के सामाप्त किए जाने पर पाटन एवं क्षति पुन उत्पन्न हुई है और इसलिए प्राधिकारी इन कैटलिस्टों के सामान्य मूल्य निर्धारण को उचित नहीं मानता है प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि पाटन की सीमा का निर्धारण करना नहीं है जबकि निर्यातक द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यातों के लिए निविदा प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लिया गया।

4. निर्यात मूल्य

प्राधिकारी ने जैड एन ओ डी एस और एल टी एस के एफ ओ बी मूल्यों का संकेत दिया है जैसे कि निर्यातक द्वारा क्रमशः *** डालर/लिटर और *** डालर/लिटर के रूप में उपलब्ध कराया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने समुद्री भाड़े समुद्री बीमा और अन्य पत्तन खर्चों पर होने वाले खर्च भी उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकारी ने एफ ओ बी मूल्यों से अन्य पत्तन खर्चों को घटाकर कारखाना द्वार निर्यात मूल्य का मूल्यांकन किया है और निर्यातक द्वारा प्रदत्त एफ ओ बी मूल्य एमुद्री भाड़े और समुद्री बीमा के आधार पर सी आई एफ मूल्य की गणना की है। प्राधिकारी ऐसा नोट करते हैं कि आयातकों यथा राष्ट्रीय मिल्स और फटिलाइजर्स लि. मुंबई भार इमउयन आयल कार्पोरेशन लि. द्वारा जबाब दायर किए गए हैं जिनमें फिर भी जांच अवधि दौरान संगत कैटलिस्टों से संबंधित सूचना नहीं दी गई है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किसी हद तक सूचना प्राप्त है और वह सूचना निर्यातक द्वारा दी गई मूल्य से संबद्ध स्थापित करती है। ज

जैड एन ओ डी एस और एल टी एस के लिए कारखाना गत निर्यात मूल्य *** डालर/किग्रा और ***/किग्रा है

5. पाटन- सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:

पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के इसी स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि की दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी; अंतर में शामिल हैं बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना जांच अवधि में कारखाना द्वार पर आधिमानित औसत निर्यात कीमत के साथ की है।

उपरोक्त निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और कारखाना गत निर्यात मूल्य के आधार पर प्राधिकारी ने भारत को निर्यात होने वाले दो कैटलिस्टों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन निम्नानुसार किया है:-

कैटलिस्ट	सामान्य मूल्य डालर/किग्रा	निर्यात मूल्य डालर/ किग्रा	पाटन मार्जिन (%)
जिक आक्साइड डिसफ्यूराइजेशन (जेड एन ओ डी एस)	***	***	146.7
न्यून तापमान शिफ्ट (एल टी एस)	***	***	240.7

उपरोक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

6. क्षति एवं कारखाना संबंध

प्राधिकारी यह नोट करते हैं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 यथा संशोधित 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को पहले ही रद्द करना चाहिए। इस प्रकार के आरोपण की तारीख से पांच वर्ष के समयावधि की समाप्ति पर इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए इसके बाद यदि समीक्षा में केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति की निव्वरता अथवा पुनरावृत्ति होती रहेगी यदि समय समग्र पर श्रम आरोपण की अवधि को आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए और यह अवधि ऐसे समयावधि बरतने संबंधी आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

बशर्तें इसके कि जहां उपर्युक्त अवधि यानि पांच वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समीक्षा प्रारंभ होती है तो यह समीक्षा समाप्ति से पूर्व किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है पाटनरोधी शुल्क की वैद्यता जारी रहेगी चाहे इस समीक्षा के नतीजे अगले एक वर्ष की अवधि तक लंबित रहे।

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-॥ के अंतर्गत जब क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावों समेत साभ संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होता।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध-II (iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन जैसे संकेतकों पर विचार किया जा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

चूंकि वर्तमान जांच के अंतर्गत यह किया जाना है कि व्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरन्तरता अथवा पुनरावृत्ति होती रहेगी प्राधिकारी ने इस पहलू का मूल्यांकन करने के लिए उपरोक्त नियम के अनुबंध-II (iv) में दर्शाए गए क्षति संबंधी उपयुक्त मापदंडों पर विचार किया है ।

प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लिए छः कैटलिस्टों से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंडों को निम्नानुसार मानते हैं-

	1998-99	1999-2000	जांच अवधि	जांच अवधि (वार्षिक मूल्य)
उत्पादन (किग्रा)	804373	556606	947561	631707.3
घरेलू बिक्री (किग्रा)	738444	396531	950668	633778.7
डैनमार्क से आयात (किग्रा)	236225	36950	180880	120586.7
न्यूनतम द्वारा मांग (किग्रा)	974669	433481	1273548	849032
कुल मांग में डैनमार्क से आयातों के शेयर%	24.24	8.53	14.21	14.21

(ख) मै. एच टी ए एस द्वारा कैटलिस्ट वार निर्यात निम्नानुसार है:-

कैटलिस्ट	1998-99	1999-2000	जांच अवधि (18 महीने)
एच डी एस	0	0	0
जेड एन ओ डी एस	164170	36950	110620
एस आर	0	0	0
एच टी एस	0	0	0
एल टी एस	72055	0	70260
मैथा	0	0	0
कुल	236225	36950	180880

(ग) प्राधिकारी यह नोट करते हैं संबद्ध कैटलिस्टों की बिक्री वसूली रूपए/किग्रा में जांच अवधि के दौरान महानिकारण मूल्य रूपए/किग्रा से नीचे है ।

(घ) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जैड एवं ओ डी एस कैटलिस्ट के संबंध में मूल जांच में अध्याय 38 और अध्याय 98 की श्रेणी अंतर्गत कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था । निर्यातक मै. एच टी ए एस एवं यूरोपीयन युनियन द्वारा इस तथ्य से संबंधित तर्क प्रस्तुत किया गया अंतिम समीक्षा यह पूर्व मान्यता रखती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना लाभकारी है विशेषता उस समय जब सारे ठ: कैटलिस्ट अंतर्गत और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं अतः प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की समाप्त करने की जांच करते हैं जो यह मानते हैं कि इस कैटलिस्ट के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू नहीं किया जा सकता है अतः इस कैटलिस्ट पर किसी प्रकार के नए पाटनरोधी शुल्क के आरोपण की सिफारिश नहीं करता है,

(ङ.) एल टी एस कैटलिस्ट के संबंध में प्राधिकारी ऐसा मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर इस कैटलिस्ट का आयात केवल अध्याय 38 की श्रेणी में आता है कुल ज्ञात मांग में 98-99 में एल टी एस का हिस्सा 7.47 है जो जांच अवधि के दौरान 5.52% हो गया । प्राधिकारी ने एस सी आई एल के अनुरोध किए जाने पर इस कैटलिस्ट का पहुंच मूल्य रूपए किग्रा में मूल्यांकन किया है इस पहुंच मूल्य की जब मूल्य के साथ डालर किग्रा में तुलना करने पर यह उपलब्ध होता है कि इस कैटलिस्ट के पाटित आयातों के कारण कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ और अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के कारण निरन्तर एवं पुनः क्षति नहीं होगी अतः प्राधिकारी इस कैटलिस्ट पर पाटनरोधी शुल्क रखने की सिफारिश नहीं करते हैं ।

(च) एच डी एस एच टी एस मैथ और एस आर के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. एच टी ए एस द्वारा मैथ मैटा एस आर के मामले या तो कोई भागीदारी नहीं रही है और अन्य दो कैटलिस्टों यथा एच डी एस और एच टी एस के मामले में मैसर्स एच टी एस के अलावा भागीदारी के कारण मूल्य में कमी हुई है । अतः मूल्य ह्रास जैसी घटना और निविदा प्रक्रिया में निर्यातक द्वारा सहमति बीच कोई कारणात्मक संबंध दिखझई नहीं देता है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एस सी आई एल द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जांच अवधि के दौरान उपयोगता उद्योग द्वारा संबद्ध कैटलिस्टों की सप्लाई से संबंधित 39 निविदाओं का मूल्यांकन किया गया था जिसमें से एस सी आई एल द्वारा 19, पी डी आई एल द्वारा 8 और विदेशी आपूर्ति द्वारा 12 जिसमें मै. एच टी एस के 8 निविदाएं शामिल हैं, निविदाओं का मूल्यांकन किया गया था प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एच डी एस कैटलिस्ट के संबंध में मै. साइनेटिक्स ने एक आदेश प्राप्त किया जब मै. एच टी एस ने इसके भाग नहीं दिया था एच टी एस के संबंध में मै. पी डी आई एल को आदेश दिया गया जबकि इसमें भी मै. एच टी ए एस की कोई सहमति नहीं थी । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान और पिछले दो वर्षों 1998-99 और 1999-2000 में इलन चार कैटलिस्टों का कोई निर्यात नहीं हुआ है ।

(छ) उपर्युक्त आर्थिक संघटक यह दर्शाता है कि संबद्ध पाटन रोधी शुल्क की समाप्त करने से घरेलू उद्योग को निरन्तर और पुनः पाटन एवं क्षति नहीं होगी और अतः प्राधिकारी संबद्ध कैटलिस्टों पर से पाटनरोधी शुल्क हटाने की सिफारिश करते हैं ।

7. पहुंच मूल्य

संबद्ध वस्तुओं के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण भारत और सी आई एफ निर्यात कीमत सीमा शुल्कों के लागू स्तर (धारा 3, 3क, 8ख, 9क) के तहत लगाए शुल्कों के छोड़कर तथा एक प्रतिशत उतराई प्रभाओं के जोड़ने के बाद किया गया है।

(घ) निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार के बाद यह देखा गया है कि:-

(क) संबद्ध देशों के मूल से अथवा संबद्ध देशों से कैटलिस्ट यथा जेड एन ओ डी एस और एल डी एस के सभी स्वरूपों का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।

(ख) विभिन्न आर्थिक संकेतक और क्षति मापदंड यह दर्शाते हैं कि संबद्ध कैटलिस्टों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से निरंतर और बार-बार पाटन एवं क्षति नहीं होगी अतः प्राधिकारी सभी छः कैटलिस्टों यथा हाइड्रोक्सिलफराइलेशन (एच डी एस) जिंक आक्साइडिसल्फ्यूराइलेशन (जेड एन ओ डी एस) हाई टैम्प्रेचर शिफ्ट (एच टी एस) टैम्प्रेचर शिफ्ट (एल टी एस) सेकण्डरी रिफायनरिंग (एस आर) और मैथानेशन (मैथ) जो डेनमार्क से भारत में निर्यात किए गए हैं, पर से पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की है।

(ग) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी
एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2002

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-Dumping investigations concerning Sunset Review of anti dumping duty on imports of Catalysts viz. Hydrodesulphurisation, Zinc Oxide Desulphurisation, High Temperature Shift, Low Temperature Shift, Secondary Reforming and Methanation Catalysts from Denmark.

No. 27/1/2001-DGAD— Having regard to the Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules as per Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 initiated Sunset Review to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on imports of Catalysts as indicated in the original preliminary findings of the Authority dated 7.5.1997 and the Custom Notification No.56 dated 20.6.1997 (hereinafter also referred to as subject goods and subject catalysts) originating in or exported from Denmark (hereinafter referred to as subject country).
- (ii) The Authority issued a public notice dated 17.1.2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations in respect of the above mentioned investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 38 and also under 98 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 originating in or exported from Denmark.
- (iii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were available in view of investigations conducted earlier) and industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2).

- (iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers ((whose details were available in view of investigations conducted earlier) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- (v) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.
- (vi) The Authority provided a copy of the initiation notification to the known exporter and the Embassy of the subject country/ European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi in accordance with Rules 6(3) supra.
- (vii) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):

(i) M/s Haldor Topsoe A/s (HTAS), Denmark

Response/information to the questionnaire was filed by the following exporters/producers:

(i) M/s Haldor Topsoe A/s (HTAS), Denmark

- (viii) The Embassy of the subject country in New Delhi and European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the known exporter was also sent to the Embassy of the subject country and European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi in accordance with Rule 6(3).
- (ix) A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6(4):-

Response/information to the questionnaire was filed by the following importers:-

- (i) M/s Rashtriya Chemicals & Fertilisers Ltd., Mumbai
- (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd., West Bengal.

- (x) Information regarding injury was sought from M/s Project and Development India Ltd. (PDIL) and M/s Sud-Chemie India Pvt. Ltd. (SCIL), the domestic producers of the subject goods. The cost of production/injury information was furnished by M/s SCIL only. M/s PDIL however gave information regarding their production of various subject catalysts in the POI.

- (xi) Request for extension was made by certain interested parties which was considered by the Authority and extension was granted upto 20.3.2002. Comments received on the same have also been duly considered in these findings.
- (xii) Cost investigation of M/s SCIL was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner. The cost data of M/s Sud-Chemie India Pvt. Ltd. was provided and analysed.
- (xiii) Additional information from M/s HTAS, the only responding exporter from Denmark was also sought.
- (xiv) An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally on 29.4.2002. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- (xv) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- (xvi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 3.9.2002.
- (xvii) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xviii) The period of investigation (POI) considered is 1.4.2000 to 30.9 2001

B. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY, EXPORTERS, IMPORTERS, USER ASSOCIATIONS AND OTHER INTERESTED PARTIES & EXAMINATION BY THE AUTHORITY

The views expressed by various interested parties have been discussed in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

1. VIEWS EXPRESSED BY M/S SUD-CHEMIE INDIA PVT. LTD. (SCIL)**a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE**

- (i) In regard to LTS, HTAS has mentioned that they are supplying special catalyst LSK. Both LSK and LK823 type catalysts have been manufactured and can not be manufactured in that way in India. This claim of M/s HTAS illustrates that HTAS is building grounds to circumvent anti dumping duty in future in case of LTS catalyst.
- (ii) HTAS resorts to offer catalysts with minor modification and calls them proprietary by changing nomenclature.
- (iii) In regard to Methanation, there is nothing revolutionary in introducing a pre-reduced catalysss. Domestic Industry can also manufacture pre-reduced or activate the catalyst before delivery. HTAS is trying to introduce a new proprietary product by circumventing anti dumping duties.
- (iv) HTAS has supplied HDS catalyst from its market subsidiary which does not attract anti dumping duties. We request the anti dumping duty to be put on this catalyst when supplied from USA also.

b) DUMPING**(i) NORMAL VALUE**

- (i) The Domestic Industry has provided information on the actual prices received from M/s Sud-Chemie AG, Germany during the period of investigation for supply of subject catalysts within the Territory of European Union.
- (ii) The domestic market of M/s HTAS is not only confined to Denmark since it does not have any user industry but to the entire Territory of European Union.
- (iii) M/s HTAS have admitted to have supplied ZnODS and LTS catalysts into India at prices which are at dumped levels. In case of ZnODS, there was no anti dumping duty in place since there were insufficient injury caused to the Domestic Industry during initial investigation though the Designated Authority had found M/s HTAS's prices were dumped prices. This scenario has changed for the worst and that injury would be found to the Domestic Industry now.
- (iv) The dumping is relevant to the normal value and not to the cost of production and that the normal value should be the price at which the HTAS supplied these catalysts in the European Union. M/s HTAS should make available these prices in the European Union to the Designated Authority.

(ii) **EXPORT PRICE**

- (i) M/s SCIL has provided tender participation details on six catalysts for the POI indicating the participation and award of tender to various participants.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) We would like to reiterate here that the Sunset Review the Designated Authority needs to take a broad view of the case to examine whether M/s HTAS will again resort to dumping their products in the absence of Anti Dumping Rules
- (ii) The Designated Authority has examined the case within the limited time frame of the period of investigation under this review. This, while enough for the Designated Authority to examine if actual dumping is occurring and the injury on Domestic Industry, is not large enough a time span to come to a conclusion as to the long term intentions of any company.
- (iii) We would also like to bring to your attention to our submission dated July 13, 2002, wherein we have provided information on M/s HTAS's dumping prior to POI under this review, and have shown M/s HTAS receiving orders for HTS catalyst at highly injurious prices. This period was outside the POI but clearly shows HTAS's intention. It was because of these orders having been procured by HTAS that PDIL and ourselves had to suppress our prices to get further orders. In actual fact, PDIL and us were not competing against each other as alleged by HTAS but were forced to reduce our prices or else lose orders to HTAS. It is pertinent to note that at the time of bidding, it is not always known who the other contenders are.
- (iv) Keeping the fact of (iii) above and a larger time frame in mind, we request the Designated Authority to continue with the Anti Dumping Duty on HTS catalyst as, in the absence of the Anti Dumping Duty, HTAS will once again resort to selling their catalyst at dumping prices.
- (v) We request that in the event of finding yourself unable to use information from outside the POI, you at least use the Non-Injurious price worked out by you for the HTS catalyst and take an undertaking from M/s HTAS that they will not supply at prices below such NIP. We are confident that M/s HTAS will refuse to do so in the event of being asked further strengthening our contention that their intention to dump at injurious prices remain.

c) **INJURY & CAUSAL LINK**

- (i) We have been able to maintain our market share and therefore there is no significant decline either in our production or in capacity utilisation or in our employment levels. However this has been achieved at the cost of having to suppress our sales price in spite of our increase in production leading to greater loss in profits as evidenced by the loss incurred in actual indigenous sales turnover for the past six years.
- (i) The catalysts-wise information and the landed value clearly indicates that there is a causal link between our performance and the existence of Anti Dumping Duty.

- (ii) Because of present anti dumping duty in case of some catalysts, we have managed to benefit by increasing our market share as also our capacity utilisation. However this alone has not been sufficient to remove injury caused to us as can be seen from the sales price compared to our cost of production.
- (iii) Injury has persisted due to our having to suppress or reduce our prices because of M/s HTAS's policy of negotiating down or quoting the very low prices in their catalysts.
- (iv) In case of ZnODS catalysts, HTAS continued to dump and that the fall in existing duty, the dumping margin has increased. The situation has now changed and we are being injured by the dumping of ZnODS.
- (v) The process of recovery has been slow for us and that five years is too short a time for anti dumping duty to have effect on the market to enable the prices to be increased. The majority of these five years have been consumed in the legal process and there has been a stiff resistance for any increase in price.
- (vi) There has been a significant effect of catalyst's life which pertains from 5 years to 12 years depending on plant design and therefore 5 years period for anti dumping duty is not sufficient to have its effect in the market.
- (vii) We are managing to retain our market share provided that if the anti dumping duties are continued for a few more years so that we will be able to increase our price in a manner which will be to our customer's satisfaction.
- (viii) The anti dumping duty as calculated on the basis of our cost of production at 70% capacity utilisation is inadequate to redress the actual market injury being suffered now by the Domestic Industry.
- (ix) The basic Customs duty has decreased to 25% which has meant the landed cost for exporter is now cheaper allowing him to further reduce its price.
- (x) HTAS's strategy has been to quote very low prices on non-proprietary catalysts and compensate the losses so incurred by selling their proprietary catalysts namely Primary Reforming Catalyst and Ammonia Synthesis Catalysts at high prices giving them unrealistic profits.
- (xi) In case of Methanation, no tender was floated during the POI. As was if HTAS has not supplied this as dumped prices because there is no demand for this catalyst.
- (xii) In case of Secondary Reforming Catalyst only one tender was floated during the POI and the order was awarded to a foreign company i.e. M/s Synthetic. HTAS did not participate in this tender at all.
- (xiii) In case of HTS we found it difficult to believe that HTAS who continued dumping in case of other catalysts will not take advantage of the situation to recommence dumping of HTS if there were no anti dumping duties.
- (xiv) Regarding price suppression, it has been mentioned by HTAS that it has been on account of internal competition amongst domestic producers. As pointed out by us, there is a definite causal link between HTAS's account of dumping and inability of the Domestic Industry to substantially increase its prices. We deny HTAS's contention that our injury is self-inflicted.
- (xv) We are not only being injured by the attitude of M/s HTAS but also the injury has increased from past levels because of factors like existing customs duties, cost of production, capacity utilisation etc. which are beyond our control.

2. IMPORTER'S VIEWS

The following submissions have been made by M/s Rashtriya Chemicals & Fertilisers Ltd., Mumbai and M/s Indian Oil Corporation Ltd., West Bengal:-

a) EXPORT PRICE

- (i) The import prices of various non-subject catalysts have been provided by M/s Rashtriya Chemicals & Fertilisers Ltd., Mumbai and M/s Indian Oil Corporation Ltd., West Bengal which are not pertaining to the subject catalysts.

3. EXPORTER'S VIEWS**A) M/S HALDOR TOPSOE A/S(HTAS), DENMARK****a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE :-**

- (i) The allegation regarding circumventing anti dumping duty on LTS is incorrect since LTS catalyst is subjected to anti dumping duty even after modification. There are no catalysts being manufactured within India today with the proprietary LSK and LK 823.
- (ii) As regards pre-reduced methanation catalyst, we have not exported the same and we have made submission that this catalyst has not been manufactured in India till date.

In response to the Disclosure Statement, the following submissions have been made :-

- (i) We agree with the Authority that the product under consideration is the six Catalysts identified in the original investigation. In regard to the LTS Catalyst, we have clearly stated that there is no attempt to circumvent the anti dumping duty on the said Catalyst. In fact, we had categorically indicated that the modified LTS Catalyst has been subjected to anti dumping duty. We had only pointed out that the modified LTS Catalyst is not manufactured in India. We agree with the Authority that the HDS Catalyst exported from USA was not within the purview of the original investigation and consequently, is not within the purview of the present Sunset Review.

b) DOMESTIC INDUSTRY

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) We submit that SCIL and PDIL do not constitute the domestic industry. It is pertinent to note that the Sunset Review has been initiated by the Authority and not at the instance of the domestic industry. Consequent on the initiation, only PDIL has come forward to support the Review. Hence PDIL cannot be treated as forming part of the domestic industry. Our submission is also reinforced by the

fact that the Authority had also examined only SCIL for the purpose of injury determination.

c) DUMPING

(i) NORMAL VALUE

- (i) The exporter has indicated that there are no sales in the home market of the six catalysts during the Period of review.
- (ii) The exporter has also provided the quantity of exports to other countries with reference to six catalysts.
- (iii) The exporter has provided details on the cost of production for the 6 catalysts during the period of investigation. The exporter has submitted that out of 4 catalysts have not been exported during the period of investigation and so there is no export price and hence the dumping margin cannot be determined.
- (iv) The cost of production of ZnODS and LTS catalysts have been provided and these are supplied at prices which covered total costs including the overheads and hence these have not been dumped.

(ii) EXPORT PRICE

M/s HTAS have provided FoB value of ZnODS and LTS catalysts and expenses incurred on account of ocean freight and pre-FoB expenses.

In response to the Disclosure Statement, the following submissions have been made by the various interested parties:-

- (i) We agree with the stand taken by the Designated Authority that the Normal Value in respect of Methanation, Secondary Reforming, HDS and HTS Catalysts need not be determined as these four Catalysts were not exported during the review period. Further, HTAS had not even participated in the tender process for two of the subject Catalysts. In any case, in the absence of export price, it is impossible to determine the Dumping Margin. Therefore, these four catalysts cannot be said to have been dumped during the period under review. The recurrence of the dumping of these four Catalysts is also a remote possibility, as has been correctly observed by the Designated Authority, as HTAS had not participated in the tender process / did not obtain any orders for these Catalysts during the period under review.
- (ii) We reiterate that the original investigation was initiated only against Denmark and not against the European Union. It is, therefore, illegal and incorrect to treat European Union as the domestic market for the purposes of review investigation. HTAS, therefore, reiterates its earlier submission that the Normal Value (for the other two Catalysts) should be determined based on the constructed value (cost of production plus profit).
- (iii) HTAS notes that the Authority has determined the normal value for the LTS and ZnODS Catalyst on the basis of domestic selling prices in Germany as provided by SCIL. HTAS had exported only 60,400 litres of LTS Catalyst and 87,200 litres of Zinc Oxide Catalyst. There were only two transactions for LTS Catalyst and 7 transactions for Zinc Oxide Catalyst. It is not known whether SCIL made

available the details of the sales of these two Catalysts through out the European Union in the 18 months period of investigation. It is our submission that SCIL had probably made available selective information, only of a few sales in Germany at higher prices, in order to distort the Dumping Margin. The information obtained by the domestic industry from their affiliates in Germany is being used to determine the normal value. Hence, the same should be used only after validation. In this connection, we invite the attention of the Authority to para 7 of Annex-II of the Agreement on Implementation of Article VI, dealing with best information available. The selective use of information by domestic industry because of their access to the data of their affiliate company in Germany cannot be ruled out. Hence, their information should be fully validated.

- (iv) To the best of our information Zinc Oxide Catalyst had not been sold within Europe during the Review period. We request the Authority to verify the claim of SCIL in this regard. We understand that there was only one order for a small quantity of 10000 litres for LTS Catalyst. The price for this quantity would appear to be negotiated with Sud-Chemi. It is our submission that the price for the LTS Catalyst is not in the ordinary course of trade as it was a single source supply, not under competitive conditions. The said price cannot, therefore, be used for determining the normal value of the LTS Catalyst.

B) EUROPEAN COMMISSION, DELEGATION OF EUROPEAN COMMISSION, NEW DELHI

a) DUMPING

The following submissions have been made by European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi:-

- (i) By using list prices in Germany from a complainant's affiliate in order to calculate the dumping margin, the Designated Authority violated Article 2.2 of the WTO Anti-Dumping Agreement which provides that the dumping margin may be "determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative. since the list prices were not prices from the exporting company – Denmark(the EU cannot be the exporting territory since the European Commission was never notified of the investigation in accordance with Article 12.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement) – and also the list prices were not "comparable" since the Danish exporter HTAS filed evidence to show that Sud-Chemie's actual prices were between 30% and 52% below its list price.
- (ii) Even if the Designated Authority was entitled to conclude that the Danish exporter had refused access to some information, it should not have disregarded the exporter's cost information. By not explaining the reasons for the rejection of the information and not properly conducting a verification of the probative value of the complainant's information which was used, the Designated Authority violated Article 6.8 and Annex II of the WTO Anti-dumping Agreement.
- (iii) By not disclosing to the Danish exporter crucial information used to calculate Normal Value and export prices and to determine the alleged injury, the

Designated Authority violated Articles 6.2 and 6.4 of the WTO Anti-dumping Agreement.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) Article 11(3) of the WTO Anti Dumping Agreement (ADA) requires that:-

“any anti dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition.....unless the authorities determine, in a review....., that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.....”

This provides pre-supposes the existence of an anti dumping duty on the product under review. However in the case of catalyst ZnODS there was none. Therefore, it is not possible to use the tests of continuation and recurrence based on the expiry of a duty, which does not exist, to justify the imposition on a higher duty rate on this product. Indeed the very inclusion of this product in the review investigation at all is highly questionable.

The European Commission submits that India can only impose a duty on znODS after a fully fledged investigation under Article 5 of the ADA.

- ii) The calculation of the Normal Value is clearly in breach of the WTO Anti-Dumping Agreement. The Agreement clearly states that where there were no domestic sales the authorities must use either ‘a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country provided that this price is reasonable, orthe cost of production in the country of origin.....’

The Indian authorities have stated that there are no sales on the domestic market, which they have identified as the European Union. However they then proceed to calculate normal value on the basis of list prices of a domestic producer in Germany. Given that there are no domestic sales in that market the authorities should have used either export prices to a third country or cost of production in accordance with the WTO Agreement. This they did not do despite the fact that the Danish exporter provided full information on the cost of production of the product concerned. In any event, it should also be mentioned that list prices of a domestic producer in Germany do not take account of discounts and other possibly significant adjustments attracted in the actual sale of a product. Furthermore it is not clear where these prices are for replacements or new equipment, a fact which appears to bear great relevance and on which India makes no finding.

d) INJURY & CAUSAL LINK

A) M/S HALDOR TOPSOE A/S(HTAS), DENMARK

- (i) M/s HTAS has not been able to obtain any order for the 4 catalysts during the period of review because of the fluid situation on account of litigation during

- which the customers have always taken into account the existence of anti dumping duties in evaluating tenders on or after imposition of the provisional anti dumping duties.
- (ii) The arguments that M/s Sud-Chemie was not able to make any price increase because of uncertainty does not represent the correct picture.
 - (iii) The Submission of M/s Sud-Chemie that they have not been able to retain or increase market price at ruinous price is again due to their own estimation while offering quotations. The injury, if any, as a result of obtained orders at these ruinous prices are self-inflicted and cannot be attributed to dumping.
 - (iv) As regards non-injurious price, depending on the optimum capacity utilisation of 70% within a period is a consistently adopted practice on determining NIP at optimal capacity utilisation. This practice has been followed in all cases
 - (v) The injury to M/s Sud-Chemie is because of the higher costs arising out of lower capacity utilisation even after imposition of anti dumping duty and it supports the contention that injury was due to reasons entirely extraneous to dumping.
 - (vi) Reduction in customs duty is a regular phenomena and that the exports have reduced prices to the extent of fall in customs duty is incorrect. The fact that HTAS did not get even one order during the period illustrates that the reduction of customs duty has in no way benefited the exporter.
 - (vii) As regards proprietary catalysts referred to by M/s Sud-Chemie, it is a normal practice for technology providers to specific certain pre-conditions such as design criteria, hardware including catalysts supplied in order to stand by the performance guarantee of the plant. These catalysts are not those under investigation and hence references to these are irrelevant.
 - viii) The injury margins were higher in previous investigation because of inclusion of M/s PDIL as a Domestic Industry. Since PDIL has not cooperated in the present investigation, the NIP would be determined on the basis of cost of production of M/s Sud-Chemie only and there would be no injury margin. Hence there is no continued injury nor can injury reoccur.
 - (ix) In a Sunset Review or Expiry Review, the Authority is required to evaluate the following two aspects:-
 - a) Whether the dumping and injury are continuing
or
 - b) Whether dumping and injury are likely to recur if the duty is withdrawn

HTAS had supplied two consignments of Low Temperature Shift Catalyst during the Period of review. One type of this catalyst was a new catalyst which had a lower rate of methanol formation. This catalyst is not being manufactured in India. Hence the export of this catalyst not produced in India, cannot cause material injury to the domestic producer.

Further the attention of the Designated Authority is invited to the fact that in the original investigation there were two domestic producers viz. PDIL and SCIL. In the present investigation, which has been initiated by the Authority on its own motion, PDIL has not extended its cooperation. SCIL is the only domestic producer whose injury recurrence is required to be analysed by the Authority. It is submitted that the fact that PDIL had not cooperated is significant and the recurrence of injury only to SCIL is required to be evaluated judicially. Since the

- recurrence of dumping and injury are to be not based on a mere conjecture or remote possibility and PDIL has chosen not to cooperate, the Authority may return a negative verdict of recurrence of dumping and injury.
- (x) It is also significant to note that SCIL had not approached the Authority with a request for initiation of the expiry review. It is because the Authority has initiated the review that they have chosen to take advantage of the situation. This is a significant aspect which shows the remote possibility of the continuation or recurrence of injury.
- (xi) We also wish to bring to the notice of the Designated Authority the submission of SCIL that during the period when the anti dumping duty was in force, orders were obtained either by them or by PDIL and that the price of the catalysts had not moved significantly because of the imposition of anti dumping duties. This submission suggests that the prices prevalent in the domestic market are determined by internal competition and is uninfluenced by the price of HTAS. If at these prices, which were prevalent during the Period of review, SCIL had suffered losses (injury), then the causal link for that injury cannot be placed on HTAS. Hence, the recurrence of injury is again a mere conjecture. Injury if any, is self-inflicted and cannot be considered as continuation of the material injury or recurrence of the material injury which presupposes the existence of a causal link between the dumping and the material injury.
- (xii) We entirely agree with the questions posed to SCIL by the Designated Authority at the hearing regarding the number of tenders that SCIL lost and whether such tenders were lost of the Domestic Industry. Since the alleged dumping has been corrected by the existence of anti dumping duties, the inability of the Domestic Industry to make good use of the opportunity shows that their injury if any, was not at all due to the alleged dumping. In fact, this reinforces our submission right through that the injury, if any, was not at all due to HTAS.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) The CIF price in Dollar per Litre and Dollar per Kg for the two Catalysts is tabulated below:-

Catalyst	FOB Price \$	Ocean Freight \$	Ocean Insurance \$	CIF \$
Zinc Oxide	3.162 / lit	0.07	0.005	3.237
LTS	5.12 / lit	0.07	0.008	5.198

- (ii) We request the Authority to use the above CIF figures for determining the landed value and to examine whether the Injury Margin is lower than the dumping margin.
- (iii) The Disclosure states reproduces the submissions of SCIL, the Delegation of the European Commission and HTAS. It is seen from para 4 – “Examination by Authority” that these submissions will be considered at for determination of injury to the Domestic Industry. In other words, there is no disclosure in regard to the existence or recurrence of injury. The Disclosure statement is flawed.
- (iv) The Authority will recall that in the original investigation HTAS had pointed out that each of the six catalysts was a distinct like product. The catalysts are not substitutable and hence the injury should be determined separately for each of the

six catalysts. The Authority did not accept this contention and had determined the injury by cumulating all the six catalysts together and had invoked Article 3.6 of the Agreement on Anti dumping. In the present investigation period, 4 of the subject catalysts had not been exported. The Zinc Oxide Catalyst should not have been included in the investigation as the duty on the said catalyst was zero in the original investigation. Since there was no anti dumping duty for Zinc Oxide Catalyst the same cannot form part of the present Review. Proviso to Section 9A (5) provides for a Review on the premise that **cessation of the duty** is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Cessation of duty presupposes the existence of anti dumping duty. There was no duty on Zinc Oxide Catalyst and hence there is no question of cessation of the duty on Zinc Oxide Catalyst. Inclusion of Zinc Oxide catalyst in the Sunset Review is incorrect.

- (v) The injury analysis is, therefore, required to be restricted only to the LTS catalyst. As the Authority had already held that it is not possible to determine injury separately for each catalyst, any injury analysis based on injury parameters for all the six catalysts would completely distort the injury analysis. The Authority cannot, therefore, determine either the existence of or recurrence of injury to LTS/Zinc Oxide Catalyst. Consequently the review should result in termination of duty on all catalysts.
- (vi) We entirely agree with the Authority, without prejudice to the foregoing, that the withdrawal of anti dumping duty on four Catalysts will not lead to recurrence of injury to the domestic injury. SCIL have argued that during the period of review they had suffered injury and that the said injury has been caused by the dumping. It is clear from their own submission that they have faced stiff resistance for any increase in price from customers. This is purely a commercial aspect and cannot be attributed to HTAS who had not supplied four of these Catalysts.
- (vii) The submission that the reduction in the Customs duties had resulted in increase in dumping margin is totally incorrect. The dumping margin is a function of normal value and export price at ex-works level which are not at all dependent on the customs duty prevailing in India. Similarly, their submission regarding low prices of non-proprietary catalysts and higher prices on proprietary catalysts is totally irrelevant to the issue and is without any basis or evidence. The provisional duty was imposed in June 1997 and the said duty had continued till today. In this scenario, it is difficult to understand the argument of SCIL that the alleged injury during the period 1997 to 2002 has been caused by HTAS. If SCIL had suffered injury during this period when four of these catalysts had not even been exported it could only mean that the injury is self-inflicted. In fact, SCIL had admitted that the injury has increased because of reduction in customs duty, increase in cost of production etc. These are the precise reasons which are required to be analysed by the Authority for determining whether the material injury was caused by reasons other than dumping. **In fact, there should be a total termination of this investigation rather than withdrawal of anti dumping duty only on four catalysts.**
- (viii) In view of the above, we request the Authority to re-examine the entire aspect of injury and causal link analysis and issue a revised disclosure. It is our submission that no injury has been caused to the domestic industry as a result of the export of the two Catalysts. Hence there is neither a present material injury nor the possibility of recurrence of material injury.

- (ix) We request the Hon'ble Authority to terminate the Sunset Review by recommending withdrawal of anti dumping duties on all the six Catalysts.

B) EUROPEAN COMMISSION, DELEGATION OF EUROPEAN UNION, NEW DELHI

- (i) By not analysing all factors having bearing on the states of the Domestic Industry as determined under Article 3.4 of the WTO Anti-Dumping Agreement the Designated Authority has violated the same article.
- (ii) By not demonstrating a causal relationship between the alleged dumped imports and the alleged injury and by failing to examine other possible causes for adverse effects on the Domestic Industry, the Designated Authority violated Article 3.5 of the WTO Anti-dumping Agreement.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) The European Commission finds the injury analysis in this case to be very weak on a number of points:
- Of the two products for which injury was found, Catalyst ZnODS should not be included in the analysis for the reasons outlined under i) above.
 - The Indian authorities have defined the 'like product' to be all six catalysts, despite the arguments of the Danish exporter. It would now appear, from the findings on injury in the review investigation, that the investigation authorities have redefined the 'like product' without explicitly admitting it. The reasoning for this assumption, on our part, is that the injury analysis finds no injury in respect of four of the six products which should imply a separation of the various modes for the purpose of injury analysis.
 - The findings contradicts the original finding that these catalysts are one like product and the WTO Rules make it clear that injury must be determined for the like product as a whole. This raises the question, whether, then two thirds of the types concerned are found to be non-injurious, how can injury be found for the remaining one third. In these circumstances, injury could only be deemed to exist if a detailed injury and causation analysis concluded, that the alleged injury by the two models concerned (in fact, only one if ZnODS is excluded) was material in the context of the whole product range. It is clear that no such analysis has been carried out.
 - A further point needs to be made in terms of the information available to the European Commission from the disclosure document and the Danish exporter. The latter has shown that its export prices to India in fact exceed its costs of production, i.e. they are not loss making. Clearly therefore any measure which is added to that price to achieve an Indian non-injurious price will identify the amount of the inefficiencies of the Indian domestic producers in comparison to their Danish counterparts. In the original investigation this ranged from 88% to 266%. With the Indian domestic producers being shown to require non-injurious prices so massively above the cost of production of

the Danish exporter, it is difficult to believe that other factors are not responsible for the injury suffered to them.

In summary, therefore, the European Commission considers that the investigation does not fulfil the requirement of Article 11 of the WTO Agreement on Sunset Reviews. The evidence on the table, little that it is, would indicate that the anti dumping proceeding on catalysts should be closed forthwith.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY:

The foregoing submissions made by the various interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and have a bearing upon the case, have been examined, considered and dealt with at appropriate places in these findings.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

The Authority notes that the present investigation is a review investigation regarding the product under consideration viz Catalysts, namely, Hydrodesulphurisation (HDS), Zinc Oxide Desulphurisation (ZnODS), High Temperature Shift (HTS), Low Temperature Shift (LTS), Secondary Reforming (SR) and Methanation Catalysts (Meth.) as also indicated in the provisional findings dated 7th May, 1997 and final determination dated 5th January, 1998 (hereinafter called original investigations) and the recommendations of which were implemented vide Customs Notification Numbers.56 of 20.6.1997 and 2 of 2.2.98 respectively. The detailed technical description of these catalysts is indicated in the original investigation and the related Custom Notifications. The subject catalysts are classified under the Customs Tariff classification 38.15 and are also cleared under Chapter 98 as project imports. Since the present investigation is only a review under Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995, the Authority holds that the scope of product under consideration is limited to the original investigation as indicated above.

The Authority noting the submissions made by M/s SCIL regarding circumvention of LTS Catalyst under different nomenclature and the HDS Catalyst being supplied in different form from USA holds that the product under consideration has been clearly indicated with technical description in the original investigation in Para E(5) to E(9) of the provisional findings dated 7.7.1997 and that any catalyst conforming to these technical details irrespective of the fact that it has a different commercial nomenclature is within the scope of product under consideration. As regards the Catalysts which has been exported from USA, the same is not within the purview of the present Sunset Review. The Authority reiterates the findings on product under consideration as indicated in Para E(5) to E(8) of preliminary findings dated 7th May, 1997 and para E(5) of the Final Findings dated 5th January, 1998.

2. DOMESTIC INDUSTRY

The Authority holds that in the original investigation M/s United Catalyst India Limited (UCIL) (Now M/s Sud-Chemie India Pvt. Ltd. (SCIL)) and M/s Projects & Development India Limited (PDIL) represented the Domestic Industry. In the present review investigation, the Authority notes that M/s HTAS has indicated that this

investigation was a suo moto review and that it has not been supported by M/s PDIL and that M/s SCIL only should be considered as Domestic Industry. The Authority in this regard notes that M/s PDIL has provided information on the production of various subject catalysts during the period of investigation and that M/s SCIL in view of its share in the total domestic production during the period of investigation represents the Domestic Industry as per Anti Dumping Rule 2(b).

3. NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

(i) FOR ZnODS and LTS CATALYSTS

The Authority notes that the submissions made by various interested parties and the response of M/s Haldor Topsoe (HTAS) indicating that the two catalysts viz. Zinc Oxide Desulphurisation (ZnODS) and Low Temperature Shift (LTS) have only been exported during the period of investigation. The Authority also notes that in respect of all the six catalysts, the exporter has indicated that there have been nil sales in Denmark and that they have provided the cost of production for the two catalysts exported to India and that they are not at the dumped price. The Authority also notes the submissions made by the European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi who have indicated that in the original investigation the list prices as referenced by the Authority were not comparable since the Danish exporter M/s HTAS filed evidence to show that that M/s Sud-Chemie's export prices were between 30% and the 52% below its list price. It has also been submitted by the European Union, Delegation of the European Commission, New Delhi that the Authority should not have disregarded the exporter's cost of production information and that by virtue of disregarding these information, the Authority had violated the Article 6.2 and 6.4 of the WTO Anti Dumping Agreement. The Authority notes that in response to the disclosure, it has been mentioned that information given by M/s SCIL is selective and that ZnODS catalyst was not sold during the period of investigation in the Territory of EU and that the LTS catalyst sales are not in ordinary course of trade.

The Authority holds that in the Review the circumstances on no domestic sales in Territory of European Union which prevailed during the original investigations also prevail as of now. The Authority has however received information with evidence regarding the domestic selling prices in Germany of M/s Sud-Chemie AG, Germany. These domestic selling prices of the two catalysts are during the period of investigation and are therefore considered as the representative domestic selling price for the normal value determination for M/s HTAS also being the best available information. The Authority also notes that vide the Supreme Court's Judgement dated 20.7.2000 the Hon'ble Court has upheld the methodology of normal value computation by the Designated Authority and that the exporter during the period of investigation should have provided the domestic selling prices prevailing in the Territory of European Union for appropriate referencing and determination of the Normal Value as settled by way of Supreme Court's judgement which was also not challenged by the exporter. However the exporter has maintained the same position as it had taken during the original investigation and further the Delegation of European Commission had also advanced the same argument. Though in response to the disclosure, M/s HTAS and EU have given views on the computation of normal value, no evidence has been provided regarding their claim, while the Authority has received appropriate evidence from the Domestic Industry

for the Normal Value computation. Under such circumstances in event of the domestic selling prices in EU being made available by M/s SCIL only for the two catalysts, the Authority has referenced the same for the purpose of the normal value determination for these two catalysts.

The Authority further holds that even if the maximum discounting of 52% as submitted by the Delegation of European Commission is considered on the domestic sales prices of M/s Sud Chemie AG, Germany as provided by M/s SCIL, there is still a definitive dumping margin witnessed in respect of these two catalysts. However no definitive information has been provided by the exporter either on their domestic selling prices in the Territory of European Union or to the third country, or else on the aspect of discounting on list prices to an extent of 30 to 52% as submitted by the Delegation of European Commission even in response to the disclosure statement. The Authority therefore holds that the methodology of determination of Normal Value is consistent in accordance with the original investigation Para F(6) of Findings dated 5 1 1998, which was also upheld by Supreme Court and also not challenged by the exporter

Keeping in view the judgement of Supreme Court, the provisions of Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff act, Annexure 1 to the Anti Dumping Rules, the Authority also does not consider it appropriate to reference the cost of production details as provided by the exporter for determination of the Normal Value but rather adopts the information as provided by M/s SCIL for Normal Value determination consistent with the original investigation.

The Normal Value for ZnODS and LTS comes to ****\$/kg. and ****\$/kg. respectively

(ii) **OTHER CATALYSTS VIZ. HYDRODESULPHURISATION (HDS), HIGH TEMPERATURE SHIFT (HTS), SECONDARY REFORMING (SR) AND METHANATION (METH.)**

With regard to the above four catalysts, the Authority notes that while there have been no exports by M/s HTAS during the period of investigation and also in the preceding two years i.e. 1998-99 and 1999-2000 as well and that there have been no participation in the tender process for exports to India in respect of the Methanation and Secondary Reforming catalysts. In respect of High Temperature Shift catalyst, the Authority notes that on the basis of the information provided by M/s SCIL, the price undercutting and suppression phenomena has been on account of internal competition from the other domestic producer and therefore there does not appear to be enough evidence to suggest that cessation of anti dumping duty would cause recurrence of injury and dumping. It is the competition from players other than M/s HTAS which have led to a situation of price depression. The Authority therefore holds that under such situation recurrence of dumping and injury on account of cessation of anti dumping duty is not conclusive and therefore does not consider it appropriate to evaluate the normal value in respect of these catalysts. As regards Hydrodesulphurisation catalyst the Authority notes that there has been participation by other exporters as well and the orders granted to them in absence of M/s HTAS's participation and the fact that during the period of investigation M/s HTAS has not been able to successfully get any order does not lead to conclusion that cessation of duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury.

The Authority therefore does not consider it appropriate to evaluate the Normal Value for this catalyst also. As regards the other two catalysts viz. Methanation and Secondary Reforming, as there has not even been any participation in the tender process for exports to India by M/s HTAS during the period of investigation, there also does not appear to be a case where cessation of anti dumping duty would lead to recurrence of dumping and injury and therefore the Authority does not propose to consider it appropriate to evaluate the Normal Value for these catalysts. Also the Authority holds that it is not feasible to evaluate the extent of dumping when there is no participation by the exporter even in the tender process for exports to India and that during the period of investigation there have been no exports.

4. EXPORT PRICE

The Authority has referenced FOB values of ZnODS and LTS as provided by the exporter as ***\$/Litre and ***\$/Litre respectively. The Authority also notes that the exporter has provided expenses incurred on account of Ocean Freight, Ocean Insurance and Port expenses. The Authority has evaluated the ex-factory Export Price by reducing the other port expenses from the FOB values and has evaluated the CIF price on the basis of the FOB price, Ocean Freight and Ocean Insurance as provided by the exporter. The Authority notes that response has also been filed by the importers viz. Rashtriya Chemicals and Fertilisers Limited, Mumbai and Indian Oil Corporation Limited, West Bengal which however have not provided the information pertaining to relevant catalysts in the POI. To the extent the information has been received from the Custom Authorities, the same has been correlated with the information provided by the exporter.

The Ex-factory Export Price for ZnODS and LTS comes to ****\$/kg. and ****\$/kg. respectively.

5. DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

The rules relating to comparison provides as follows:

“While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability ”

The Authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of dumping margin.

Based on the normal value and the ex-factory export price as determined above the Authority has evaluated the dumping margin for the two catalysts exported to India as follows:-

Catalysts	Normal Value \$/kg	Export Price \$/kg.	Dumping Margin(%)
Zinc Oxide Desulpherisation (ZnODS)	***	***	146.7
Low Temperature Shift(LTS)	***	***	240.7

The above dumping margins are above the de-minimus limits

6. INJURY AND CAUSAL LINK

The Authority notes that as per Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 “the anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provides further that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year”.

Also under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, “...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

Since under the present investigation it is to be evaluated as to whether cessation of anti dumping duties would lead to continuance or recurrence of dumping and injury, the Authority has considered appropriate injury parameters as indicated in Annexure II(iv) of the Rules supra to evaluate this aspect.

The Authority observes the various economic parameters pertaining to the six catalysts for the Domestic Industry as under:-

(a)

	1998-99	1999-2000	POI	POI (Annualized)
Production (Kg)	804373	556606	947561	631707.3
Domestic Sales (Kg)	738444	396531	950668	633778.7
Imports from Denmark (Kg.)	236225	36950	180880	120586.7
Minimum known demand (Kg.)	974669	433481	1273548	849032
% share of imports from Denmark in the known demand	24.24	8.53	14.21	14.21

(b) The catalyst-wise exports by M/s HTAS are as follows:-

			(in Kgs)
Catalysts	1998-99	1999-00	POI (18 months)
HDS	0	0	0
ZnODS	164170	36950	110620
SR	0	0	0
HTS	0	0	0
LTS	72055	0	70260
Meth	0	0	0
Total	236225	36950	180880

(c) The Authority notes that the Net Sales Realisation in Rs/kg. of the subject catalysts has been below the NIP in Rs/kg during the POI.

(d) The Authority notes that in respect of ZnODS catalyst since in the original investigation there was no anti dumping duty imposed under Chapter 38 and also under Chapter 98 category. The arguments made by exporter viz. M/s HTAS and EU regarding the fact that the Sunset Review presupposes the existence of anti dumping duty holds merit especially when all the six catalysts are not interchangeable and substitutable and therefore the Authority holds the test of cessation of anti dumping duty which presupposes the existence of anti dumping duty cannot be applied for this catalyst and therefore does not recommend imposition of any new anti dumping duty on this catalyst.

- (e) As regards LTS catalyst, the Authority holds that as per the evidence made available by the Domestic Industry, the imports of this catalyst have taken place under Chapter 38 category only. The % share of LTS in total known demand was 7.4% in 1998-99 which decreased to 5.52% in POI. The Authority has evaluated landed value in Rs/kg for this catalyst as also requested by M/s SCIL. This landed value when compared with the Non-Injurious Price in \$/kg implies that there is no price undercutting on account of dumped imports of this catalyst and therefore the Authority holds that in this case, the cessation of anti dumping duty would not lead to continuance and recurrence of injury. The Authority therefore does not recommend continuance of anti dumping duty on this catalyst.
- (f) As regards the other four catalysts, viz. HDS, HTS, Meth. and SR, the Authority notes that there has either been no participation by M/s HTAS viz. in case of Meth. and SR and as regards the other two catalysts viz HDS and HTS, the price undercutting has been on account of players other than M/s HTAS thus therefore does not imply any causal link between the phenomena of price undercutting and the participation by the exporter in the tender process. The Authority notes that it has been mentioned by M/s SCIL that 39 tenders were evaluated pertaining to the supply of subject catalysts by the user industry during the period of investigation of which 19 were obtained by M/s SCIL, 8 by M/s PDIL and 12 by foreign suppliers including 8 by M/s HTAS. The Authority also notes that in respect of HDS catalyst, M/s Syntex had obtained an order when there was no participation by M/s HTAS. Also in respect of HTS, the orders were placed on M/s PDIL when M/s HTAS did not participate. The Authority notes that there are no exports of these 4 catalysts during the period of investigation and also in the preceding two years i.e. 1998-99 and 1999-2000..
- (g) The above economic indicators imply that the cessation of anti dumping duty on the subject catalysts will not lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry and therefore the Authority recommends discontinuance of the anti dumping duty on all the subject catalysts.

7. LANDED VALUE

The landed value has been determined for the subject goods after adding on weighted average CIF export price, the applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges.

D. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing that:

- (a) The catalysts viz. ZnODS and LTS in all forms originating in or exported from the subject country have been exported to India below its normal value;

- (b) The various economic indicators and injury parameters imply that the cessation of anti dumping duty on the subject catalysts will not lead to continuance or recurrence of dumping and injury and therefore the Authority recommends discontinuance of dumping duty on all the six catalysts viz. Hydrodesulphurisation (HDS), Zinc Oxide Desulphurisation (ZnODS), High Temperature Shift (HTS), Low Temperature Shift (LTS), Secondary Reforming (SR) and Methanation (Meth.) exported to India from Denmark.
- (c) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority
and Addl Secy.

